

बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद भड़का बवाल, धारा 144 लागू

बिलासपुर। शहर में मामूली विवाद के बाद भड़के बवाल को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है।

बिलासपुर शहर में बीती रात मामूली निजी विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही एसएसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल देर रात मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

बवाल के बाद पुलिस ने सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की भड़काऊ, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संभागायुक्त सुनील जैन ने बताया दो लोगों के व्यक्तिगत विवाद को गुटबाजी के रूप में परिवर्तित किया गया। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तत्काल



कार्रवाई की है। शांतिपूर्वक दुकानें और मार्केट खुला है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पथराव की घटना में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। वहीं, दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों को भी चोटें आई हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।

आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कोतवाली क्षेत्र में दो गुटों के बीच लड़ाई झगड़ा और पथरबाजी हुई। पुलिस प्रशासन ने पूरी रात फ्लैगमाचं निकाला। स्थिति नियंत्रण में है। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घायल पुलिस अधिकारियों का इलाज चल रहा है। आरोपियों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। बिलासपुरवासियों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे।

घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। ड्रोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती जारी है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अपवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। पुलिस ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वाइन फ्लू के लिए तैयार है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल

जांच की सुविधा के साथ आइसोलेशन वार्ड भी बनाया

कोरबा। प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य बुखार की तरह ही होते हैं लेकिन बुखार लगातार बने रहने पर स्वाइन फ्लू का खतरा हो सकता है। मरीजों को जांच की सलाह दी जा रही है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइल फ्लू की जांच और इलाज की तैयारी कर ली गई है। वायरस की जांच के लिए अलग लैब बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है।

फिलहाल कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके मामले सामने आए हैं जबकि कुछ मरीज कोरबा जिले के निवासी हैं लेकिन उनका इलाज रायपुर में चल रहा है, जिन्हें भी अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरबा जिले से स्वाइन फ्लू के कुल मिलाकर 5 मरीज सामने आ चुके हैं लेकिन फिलहाल केवल एक मरीज एक्टिव है। संक्रमण न फैले इसके लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है।



मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ गोपाल सिंह कंवर ने बताया अस्पताल में स्वाइन फ्लू के जांच की पूरी सुविधा है। अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर लिया गया है, हालांकि फिलहाल हमारे पास कोई मरीज नहीं हैं, लेकिन सक्रिय मरीज बढ़ने की स्थिति में हमारे पास पूरी तैयारी है।

स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्वाइन फ्लू में जांच की पुष्टि होने पर मरीज जब तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है। तभी उसे स्वाइन फ्लू की दवा दी जाती है, सामान्य तौर पर यह आम बुखार की तरह होता है, लेकिन लगातार बुखार बने रहने पर जब निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तब मरीज की जांच

में पुष्टि के बाद स्वाइन फ्लू की दवा दी जाती है। सामान्य तौर पर पहले दूसरे स्टेज में मरीज बुखार वाली दवा से ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन का पालन करते हुए मरीजों की जांच एवं इलाज के लिए तैयारी करने का दावा कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के बीच चिकित्सकों ने वायरल फीवर से पीड़ित लोगों को लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी है। लगातार बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या अन्य संबंधित लक्षण बने रहने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने और जल्द पड़ने पर एच।एन।1 की जांच कराने पर जोर दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते कदम

स्वयं की मेहनत और सरकारी सहयोग से कमलेश यादव बनीं ‘लखपति दीदी’

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कभी अपने छोटे-से व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सपना देखने वाली श्रीमती कमलेश यादव आज आत्मनिर्भरता और सफलता की मिसाल बन चुकी हैं। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत मंडरागावा की कमलेश यादव वंदना महिला स्वसहायता समूह से जुड़ीं और समूह की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी मेहनत को नई दिशा दी। स्वसहायता समूह से जुड़ने के बाद कमलेश को आरएफ, सीआईएफ और बैंक लोन के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिला। इस सहयोग का बेहतर उपयोग करते हुए उन्होंने चिकन स्टोर का व्यवसाय शुरू किया। इसके साथ ही वे सिलाई का कार्य भी कर रही हैं। आय के दो साधनों ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कमलेश की मेहनत, लगन और सही अवसरों के मेल का परिणाम है कि आज उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है। अपनी इस उपलब्धि के साथ वे ‘लखपति दीदी’ के रूप में नई पहचान बना रही हैं। कमलेश यादव का कहना है कि महिला स्वसहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन में बदलाव का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। समूह के माध्यम से मिले वित्तीय



सहयोग ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और अपने हुनर को व्यवसाय में बदलने का अवसर दिया। अपनी सफलता के लिए कमलेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिल रहा सहयोग उनके जैसे अनेक परिवारों के लिए नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार कर रहा है। कमलेश यादव के कहनाी आज गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है कि स्वसहायता समूह से जुड़कर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुआ जा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी बनाई जा सकती है।

कोरबा में झमाझम बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल

कोरबा। कोरबा में शनिवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। तेज बारिश से शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए और नाली-नाले का गंदा पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खाने-पीने का सामान बर्बाद हो गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

पिछले पांच दिनों से मौसम बदला हुआ था और रुक-रुककर बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने स्थिति बिगाड़ दी। सुबह होते ही कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और सड़कों व नालों का पानी घरों में घुटनों तक भर गया। लोग खुद ही पानी निकालने में जुटे रहे।

नगर निगम क्षेत्र के आरपी नगर, चिमनी भट्टा, शारदा विहार, अमरैया पारा, मोती सागर पारा, सीतामणी और मुंडापार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चिमनी भट्टा में 40 से अधिक घरों में नाले का पानी कमरों तक घुस गया। पहले पानी मुख्य द्वार तक था, अब घरों के अंदर भर गया है। इससे घरों का सारा सामान, बच्चों की कांपी-कितारें और खाने-पीने का सामान भीगकर खराब हो गया। लोगों के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया।



शारदा विहार अटल आवास में 12 से अधिक घरों में नाली और नाले का गंदा पानी घुस गया। गली पूरी तरह जलमग्न हो गई और घरों का सामान पानी में तैरता नजर आया।घरों के अंदर सांप बिछुड़ गंदगी भी घुस गए। लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन स्थायी समाधान नहीं निकाल रहे।

स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन और नगर निगम को जल निकासी और नाली सफाई की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्ड नंबर 14 चिमनी भट्टा और अमरैया पारा हर साल जलभराव से जूझता है, फिर भी निगम ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।

घोटुलों में चार दशक बाद एक बार फिट गूंज रही मांदर की थाप

नारायणपुर। जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीण चार दशक तक नकसली हिंसा और भय के साये में अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर रहे, लेकिन अब फिर अपनी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। कभी शाम होते ही गांवों में छा जाने वाला सनाटा अब कई जगह मांदर की थाप और पारंपरिक गीतों से टूट रहा है। घोटुलों में चेलिक और मोटियारिनों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। युवा पारंपरिक नृत्य और गीतों के जरिए अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उस सामाजिक जीवन को वापसी है, जो लंबे समय तक नकसल हिंसा के कारण प्रभावित रहा। अब घोटुल की रौनक अबूझमाड़ में बदलते माहौल और लौटते भरोसे की तस्वीर बन रही है।

अबूझमाड़ में लंबे समय तक नकसल हिंसा का असर केवल सुरक्षा और आगमन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ा, शाम होते ही ग्रामीण घरों में सिमट जाते थे।

बस्तर के चित्रकोट-तीरथगढ़ जलप्रपात में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही

जगदलपुर। मानसून में चित्रकोट जलप्रपात इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, 15 अगस्त के बाद से यहां पर्यटकों की बड़ी संख्या लगातार बनी हुई है। शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, कि पार्किंग स्थल में जगह कम पड़ जाती है। कई लोगों को अपनी गाड़ियां जलप्रपात से काफी दूर खड़ी करनी पड़ती हैं। बड़ी संख्या में परिवार, युवा और दूसरे राज्यों से आए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मानसून में पानी बढ़ने से चित्रकोट जलप्रपात पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। कांगेर घाटी क्षेत्र का तीरथगढ़ जलप्रपात भी मानसून में पर्यटकों को पसंद बना हुआ है, जहां सीढ़ीनुमा चट्टानों से गिरता पानी देखने के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। चित्रकोट जलप्रपात के साथ तीरथगढ़ और बस्तर के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी पर्यटक अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हैं।

बस्तर आने वाले पर्यटक अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल तक



सीमित नहीं रहे रहें हैं। चित्रकोट, तीरथगढ़ सहित आस-पास के कई प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों की सैर कर रहे हैं। पिछले सप्ताह रायगढ़ से बाइक राइडर्स की एक टीम बस्तर पहुंची। टीम ने बस्तर स्थलों को भी सोशल मीडिया पर दिखाया। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि बस्तर अब शांत है और पर्यटक यहां बेफिक्र होकर घूमने आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बस्तर की तस्वीरें और वीडियो लगातार पहुंचने से दूसरे शहरों और राज्यों के लोगों में भी यहां घूमने को लेकर रुचि बढ़ रही है। यही वजह है कि इस मानसून में बस्तर के पर्यटन स्थलों पर बाहरी पर्यटकों की मौजूदगी पहले के मुकाबले ज्यादा नजर आ रही है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

ऑनलाइन सट्रे पर शिकंजा फरार आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 12 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 22 फरवरी को पुलिस की सूचना मिली थी कि तक्रियापारा स्थित सोहेल अहमद खान के मकान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा खिलैया जा रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर सोहेल अहमद खान और संतोष कुमार गोंड को पकड़ा था। इस दौरान मौके से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने में इस्तेमाल होने वाला 01 लैपटॉप, 01 एलईडी टीवी, 04 मोबाइल फोन, 01 डीवीआर, नगदी रकम 5,000 रुपये सहित कुल 2,70,500 रुपये की सामग्री जब्त की गई थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे में सलिस सोहेब अख्तर, साहिल, विजेन्द्र कुमार सहित अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था।

पोटाकेबिन की 47 छात्राएं बीमार अस्पताल में इलाज जारी

सुकमा। जिले के बालिका पोटाकेबिन पोलमपल्ली की 47 छात्राओं के दो दिन में अचानक बीमार होने से हड़कंप मच गया है। छात्राओं को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद उपचार के लिए दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इनमें से एक छात्रा को सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद कुछ छात्राएं स्वस्थ होकर पोटाकेबिन वापस लौट चुकी हैं, जबकि 23 छात्राओं का दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। वहीं, एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि पोटाकेबिन पोलमपल्ली में करीब 350 छात्राएं अध्ययनरत हैं। लगातार छात्राओं के बीमार पड़ने के बाद संस्थान की भोजन, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल छात्राओं के बीमार पड़ने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

बाइक की हुई टक् से मिड़त तीन युवकों की मौत

बिलासपुर। शनिवार को सुबह तखतपुर के जूनापारा में मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों की बाइक टक् से जा भीड़ी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद टक् चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही जूनापारा चौक पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। समाचार लिखे जाने तक मृतक युवकों की पहचान नहीं हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक जूनापारा क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी एक टक् से उनकी मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक और शव पड़े होने से कुछ समय के लिए रास्ते पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। जानकारी मिलते ही जूनापारा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मृतकों की पहचान करना है।

सिरगिट्टी में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की

बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का हरदी कला टोना इलाका एक ही रात दो गंभीर वारदातों से दहल उठा। पहली घटना में मामूली विवाद में छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की जान ले ली। वहीं दूसरी घटना में शराब दुकान के बाहर युवकों के बीच हुआ विवाद चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें एक युवक पर प्राणघातक हमला किया गया। दोनों घटनाओं के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हरदी गांव के सूर्यवंशी मोहल्ले की घटना है, जहां सुभाष कुरै, उम्र 38 वर्ष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राखी बांधने के लिए सुभाष की बहन व उसका भांजा घर आए थे। इसी दौरान सुभाष के छोटे भाई सुदर्शन कुरै ने अपने भांजे से विवाद करते हुए कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी। भांजे से मारपीट करते देख सुभाष बीच-बचाव करने पहुंचा। इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया। तैश में आए सुदर्शन ने सब्बल से अपने ही भाई सुभाष पर वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि सुभाष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी सुदर्शन फरार हो गया।

ज्वेलरी शॉप में चोरी, ग्राहक बनकर आए 3 शायितर

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी से ज्वेलरी शॉप में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राहक के भेष में आए तीन शायितरों ने ज्वेलर की आंखों में धूल झांकते हुए 2 लाख से ज्यादा का सोने का चेन पार कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मकई चौक स्थित शनि मंदिर के पास आमंत्रण ज्वेलर्स है। दुकान में दो महिला सहित तीन लोग ग्राहक बनकर पहुंचे और बड़े शौक से सोने चांदी के आभूषण देखने लगे। इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने 17 ग्राम सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। चोरी हुए सोने की चेन की कीमत 2 लाख 22 हजार रुपए बताई जा रही है। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तीनों आरोपी ग्राहक बनकर आभूषण देखते और फिर चोरी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की मानें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। तीन दिन पहले जगदलपुर में भी ठीक इसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

बेमेतरा में गिरौदपुरी के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी

- 13 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर**

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में शनिवार को एक बार फिर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ने बड़ा हादसा करा दिया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 13 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है।

प्रतापपुर के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव के रहने वाले एक परिवार के सदस्य पिकअप वाहन में सवार होकर गिरौदपुरी धाम दर्शन के लिए



रवाना हुए थे। वाहन में करीब 25 श्रद्धालु सवार थे। इस दौरान प्रतापपुर के पास अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वाहन में सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और

राहगीर मौके पर पहुंचे तथा घायलों को बाहर निकालने में मदद की।

सड़क दुर्घटना में कुल 13 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की वास्तविक वजह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन

- योजना की जानकारी दी जायेगी, उपभोक्ताओं से आवेदन भी लिए जायेंगे**

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने के साथ ही उनसे आवेदन प्राप्त करने के लिए जिले के शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

जिला पंचायत सीईओ एवं योजना के नोडल अधिकारी श्री हरीश मंडावी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत आवासीय परिसरों में उपभोक्ताओं को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने के साथ ही उनसे



आवेदन प्राप्त करने के लिए 01 सितंबर मंगलवार को नरहरपुर के तहसील कार्यालय परिसर में शिविर लगाया जाएगा। इसी प्रकार 02 सितंबर बुधवार को न्यू कम्युनिटी हॉल कांकेर में और 03 सितंबर गुरुवार को नगर पंचायत चारामा में बस स्टैंड के बाजू स्थित गांधी मैदान में शिविर लगाया जाएगा। सोलर

प्लांट लगवाने पर 01 किलोवाट क्षमता के लिए 45 हजार रुपए, 02 किलोवाट क्षमता के लिए 90 हजार रुपए और 03 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने पर 01 लाख 08 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। उपभोक्ता इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने घरों में सोलर प्लांट लगवा सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

विवेक आचार्य बनाए गए राज्य वन विकास निगम लि. के कार्यकारी संचालक

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री



विवेक आचार्य, भा.व.से. (2006) प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, रायपुर की सेवायें वन विभाग को वापस लौटाये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री विवेक आचार्य को प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ किया है। उक्त आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

महाराष्ट्र मंडल में बैल सजाओ

प्रतियोगिता 11 को

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल परिसर में 11 सितंबर को तान्हा पोळा पर्व पर बैल सजाओ स्पर्धा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति समिति की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र मंडल के सभासदों के अलावा पहली बार बाहरी समाज व संस्थाओं के प्रतिभागियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। नए कार्यकाल की पहली बैठक में संस्कृति समिति की प्रमुख गौरी क्षीरसागर ने अपने आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार प्रतियोगिता आयु के आधार पर तीन वर्गों में होगी। पहला वर्ग पांच साल के बच्चों तक के लिए होगा। दूसरा वर्ग 11 साल तक के बच्चों के लिए होगा और तीसरा ओपन कंपटीशन रहेगा। प्रतियोगिता के लिए बैल की सजावट, प्रसाद, प्रतिभागी के परिधान से लेकर अन्य कई कटेगरी में अंक निर्धारित किए गए हैं। उसी के आधार पर प्रतियोगिता के निर्णायक विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान के प्रतिभागी के नाम घोषित करेंगे। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण क्षीरसागर, समीर टड्डू, डॉ. बबोता बितलें, प्रेम उपवंशी, प्रशांत बक्षी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उमिया मार्केट में 33/11 केवी

नवीन उपकेंद्र का लोकार्पण

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नगर संभाग (उत्तर) द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत भनपुरी स्थित उमिया मार्केट में निर्मित 33/11 केवी नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण हुआ। पांच एमवीए क्षमता वाले इस उपकेंद्र से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मोतीलाल साहू थे। इस अवसर पर जोन क्रमांक 1 के अध्यक्ष श्री गज्जू साहू सहित पार्षद श्री नंद किशोर साहू, श्री भागत राम हरवंश, श्री मनमोहन मनहरे, श्रीमती अंबिका साहू तथा एल्डरमैन श्री विक्रम सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि उपकेंद्र के निर्माण में 5 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर के साथ 0.6 किलोमीटर 33 केवी लाइन तथा 1.7 किलोमीटर 11 केवी लाइन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 2.31 करोड़ रुपये की लागत आई है। उपकेंद्र के ऊर्जाकृत होने से घरेलू एवं व्यावसायिक निम्नदाब उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

आरबीआई ने आयोजित किया वित्तीय साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम



करने और उन्हें डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने की दिशा में माता सुंदरी पब्लिक स्कूल, रायपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के मार्गदर्शन में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग की महाप्रबंधक श्रीमती नम्रता शुक्ला, एजीएम श्री हेमंत एवं एएम श्री राहुल तथा भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर से एएम श्रीमती नम्रता मेहुरिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिला अग्रणी बैंक कार्यालय, रायपुर से एलडीएम श्री मोहम्मद मोफिज एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र रायपुर के एफएलसी श्री दिलीप कुमार यदु ने भी सहभागिता की। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की विशेष पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बैंकिंग सेवाओं के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग, बचत की आदत, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन तथा वित्तीय जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में वित्तीय अनुशासन अपनाने और बैंकिंग सेवाओं का समझदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी होने की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर शिकायत करने से साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई में मदद मिल सकती है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

सेवा संकल्प उत्सव को लेकर भाजपा की राज्य स्तरीय कार्यशाला

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी

रायपुर। सेवा संकल्प उत्सव अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को हो रहा है। प्रदेश स्तरीय इस कार्यशाला के आयोजन में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, राष्ट्रीय मंत्री डॉ। कविता पाटीदार, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और अभियान के सदस्य ओपी चौधरी मौजूद हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले दिनों में जनता के बीच चलाए जाने वाले सेवा कार्यक्रमों की योजना बनाना है।

यह विशेष अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक पूरे एक



महीने चलेगा। बैठक के दौरान इस अवधि में होने वाले अलग-अलग तरह के सामाजिक, रचनात्मक और जनता की भलाई से जुड़े कामों की रूपरेखा तय की गई। इसके साथ ही, जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अलग-अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां भी दी जा रही है।

सांसद संतोष पांडे ने कहा जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तब

वहां दूसरी पार्टी की सरकार होने के बावजूद मोदी जी ने राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले पीड़ितों की सेवा का संकल्प पूरा किया था, भाजपा इसी सेवा भावना के साथ समय-समय पर जनता के बीच काम करती रहती है।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि सेवा संकल्प अभियान के जरिए पार्टी अपने अंत्योदय के मूल मंत्र को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इसके लिए क्यों चिंतित हो रही है, सेवा के लिए भाजपा हमेशा तत्पर रही है। अंत्योदय का मंत्र बीजेपी ने दिया है और हमारे जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय के समय से हम सेवा का संकल्प लेकर चले हैं।

बिलासपुर में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में शुक्रवार देर रात हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। सड़क में धारा 307 और 191 भी शामिल की गई है। आरोपियों की पहचान के लिए ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रित होने का दावा किया जा रहा है और एसएसपी के साथ कलेक्टर मामले में निगरानी कर रहे हैं।

बता दें कि बीती देर रात शहर में मामूली विवाद ने देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद स्थिति को

लाभांडी से कचना होते हुए सड़डू तक बनेगी नई सड़क

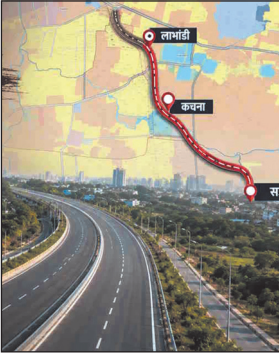
■ 3 लाख लोगों को होगा फायदा

रायपुर। राजधानी रायपुर के 2021 के मास्टर प्लान में तय की गई एमआर 43 सड़क का काम बहुत जल्द शुरू होगा। लाभांडी से कचना होते हुए सड़ तक बनेने वाली करीब तीन किलोमीटर की नई सड़क के लिए लैंड यूज चेंज करने अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नई सड़क के बनने से तीन लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा।

लाभांडी, कचना, सड्डू और बलौदाबाजार की ओर जाने वाले लोगों का कम से कम 20 मिनट समय बचेगा। उन्हें किसी जाम में भी नहीं फंसना होगा। नई सड़क बनने के बाद सड्डू, कचना और विधानसभा रोड पर भी लगातार बढ़ा रहा ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र भारद्वाज की ओर से जमीन के खसरा नंबरों के साथ शुक्रवार को इसकी सूचना अखबारों में जारी की गई है। इसमें शहर के दो बड़े बिल्डरों की जमीन भी दायरे में आ रही है। इस सूचना में दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय के बाद किसी भी तरह की आपत्ति मंजूरी नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि रायपुर के 2031 के मास्टर प्लान में भी इस सड़क को शामिल किया गया है। यही वजह है कि राज्य सरकार इस सड़क को बनाने के लिए जल्द फैसले ले रही है। लोग अपनी



अधिग्रहण किया जा रहा है। यह जमीन अभी आवासीय है। इसके लैंड यूज परिवर्तन कर इसे मिश्रित किया जा रहा है। तीन किलोमीटर इस लंबी सड़क का निर्माण रायपुर विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग वाले करेंगे। लाभांडी, कचना, सड़ होते हुए इस सड़क को बलौदाबाजार जाने वाली सड़क से मिलाया जाएगा।

नई सड़क बनने से वीआईपी स्टेट खम्हारडीह, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड, पिरदा, बारांडेरा, जोरा, चंडीनगर, पार्वती नगर और भावना नगर जैसे इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। आठ से ज्यादा वाडों के करीब तीन लाख लोग सीधे रिंग रोड से जुड़ सकेंगे। लोगों को ट्रैफिक सिग्नल और जाम से राहत मिलेगी। केवल कचना के ही इलाके में 20 से ज्यादा नई कॉलोनियां बन रही हैं।

आपत्तियों को कलेक्टोरेट, स े ब ा ग क मिशनर , टाउन प्लानिंग और निगम दफ्तर में कर सकते हैं।

नई सड़क के लिए 99 100 हेक्टेयर जमीन का

अधिग्रहण किया जा रहा है। यह जमीन अभी आवासीय है। इसके लैंड यूज परिवर्तन कर इसे मिश्रित किया जा रहा है। तीन किलोमीटर इस लंबी सड़क का निर्माण रायपुर विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग वाले करेंगे। लाभांडी, कचना, सड़ होते हुए इस सड़क को बलौदाबाजार जाने वाली सड़क से मिलाया जाएगा।

नई सड़क बनने से वीआईपी स्टेट खम्हारडीह, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड, पिरदा, बारांडेरा, जोरा, चंडीनगर, पार्वती नगर और भावना नगर जैसे इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। आठ से ज्यादा वाडों के करीब तीन लाख लोग सीधे रिंग रोड से जुड़ सकेंगे। लोगों को ट्रैफिक सिग्नल और जाम से राहत मिलेगी। केवल कचना के ही इलाके में 20 से ज्यादा नई कॉलोनियां बन रही हैं।

आपत्तियों को कलेक्टोरेट, स े ब ा ग क मिशनर , टाउन प्लानिंग और निगम दफ्तर में कर सकते हैं।

नई सड़क के लिए 99 100 हेक्टेयर जमीन का अधिसूचना 11 अगस्त को जारी की गई है। इस नई कॉलोनी को लाभांडी, सड्डू, कचना और बलौदाबाजार रोड से जोड़ने के लिए ही एमआर 43 नई सड़क बनाई जा रही है। नई सड़क बनने के बाद पिरदा और तुलसी गांव में बनने वाले नई टाउनशिप के लोग आसानी से इन सभी मुख्य सड़कों तक जा सकेंगे। इससे टाउनशिप की जमीन की खरीदी-बिक्री भी बढ़ेगी।

अनिवार्य सुरक्षा उपकरण: प्रत्येक पूजा पंडाल में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे और चालू हालत में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। अल्कोहल टेस्ट व बीएनएस की धाराएं: विसर्जन नाचों में नशे में धुत होकर शामिल होने वालों पर कड़ी दृष्टि रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन के पास संदिग्धों का स्थल पर ही अल्कोहल टेस्ट करने का अधिकार होगा।

सर्वजनिक उपद्रव पर कार्रवाई: नशे की हालत में पाए जाने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 355 (सर्वजनिक स्थल पर अनुचित आचरण) के तहत मामला दर्ज होगा। वहीं, अश्लीलता फैलाने या फूहड़ प्रदर्शन करने पर आयोजकों एवं दोषियों के खिलाफ धारा 296 (सर्वजनिक उपद्रव) के तहत कलोट दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

यूसीसी पर कांग्रेस के प्रदर्शन की चेतावनी पर सांसद संतोष पांडेय का पलटवार

कहा- सफल नहीं होंगे मंसूबे

रायपुर। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का विरोध भी मुखर होता जा रहा है। विषय पर कांग्रेस के प्रदर्शन की चेतावनी पर सांसद संतोष पांडेय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली जैसी स्थिति यहां भी बनाना चाहती है। कांग्रेस समय-समय पर अराजकता फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं होगी।

सांसद संतोष पांडेय ने मीडिया से चर्चा में यूसीसी पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि बीजेपी लगातार शांति कायम करने का काम कर रही है। कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर आगेगी, उसे जनता जवाब देगी। कांग्रेस भ्रम फैलाने और लोगों को भड़काने का काम कर रही है। हमारे यहां आदिवासी मुख्यमंत्री और महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं।

वहीं सेवा संकल्प अभियान पर कांग्रेस के बयान पर सांसद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि कई कमियों के बावजूद महाराष्ट्र और बिहार में हमारी सरकार क्यों बनी? जो लोग यह मुद्दा उठाते हैं, वे



खुद ही पिटते हैं। कांग्रेस कोई भी मुद्दा लेकर आए, सफल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता पसंद करती है।

वहीं महादेव सट्टा ऐप के मामले में कार्रवाई को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। मैंने सबसे पहले लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को सट्टे और शराब के नशे में धकेला। हमारी सरकार युवाओं को सही दिशा देने का काम कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बिलासपुर हिंसा को लेकर भूपेश ने सरकार पर साधा निशाना

■ बोले- गृह मंत्री अक्षम, मंत्रियों की वन-टू-वन बैठक पर भी तंज

रायपुर। बिलासपुर में हुई हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गृह मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है और अपना जिला भी नहीं संभल रहा। भूपेश बघेल ने कहा, इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री अक्षम हैं। गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, अपना जिला नहीं संभल रहा है। स्थिति लाचार और खराब है। ये सिर्फ वसूली में लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगा देना आसान है, लेकिन कार्रवाई करना अलग बात है। बघेल ने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए केवल आरोप लगाए जा रहे हैं।

बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात दो पक्षों के विवाद के बाद स्थिति बिगड़ गई थी। कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी की बात फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई गाड़ियों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा।



भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। पथराव में तारबाहर टीआई रवि तिवारी के सिर में चोट लगी। एक आरक्षक समेत कई लोग घायल हुए। स्थिति को संभालने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह हेलमेट पहनकर मौके पर पहुंचे। जांजगीर-चांपा, मुंगेली और सीएएफ से अतिरिक्त बल बुलाया गया। तड़के करीब 4 बजे तक थाने और आसपास के इलाकों में भीड़ जुटी रही।

पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज खंगाल रही है। दोनों पक्षों के नामजद लोगों समेत अन्य आरोपियों के

शक्कर के बढ़ते कीमतों के विरोध में कांग्रेस करेगी ‘चीनी सत्याग्रह’

रायपुर। शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस अब ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। पार्टी जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सड़क पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि देश में गन्ने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित इंधन से वाहनों को नुकसान हो रहा है। गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में होने के कारण शक्कर की आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि सरकार शक्कर की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से अनजान नहीं थी। सरकार को तीन-चार महीने पहले ही स्थिति का अंदाजा था, इसके बावजूद कीमतों को नियंत्रित करने के



लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बैज ने आरोप लगाया कि महंगाई बढ़ाकर सरकार जनता से करीब 36 हजार करोड़ रुपये वसूल चुकी है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है।

दीपक बैज ने कहा कि एक समय नमक की कीमत बढ़ने के विरोध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था। आज शक्कर की कीमतों में बढ़ोतरी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस आने वाले दिनों में ‘चीनी सत्याग्रह’ शुरू करेगी।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने गृहमंत्री को सौंपा गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन

■ लागू कराने की मांग, अश्लील गानों एवं फूहड़ नृत्य पर कानूनी कार्रवाई का आग्रह

रायपुर। गणेशोत्सव पर्व को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल स्वरूप प्रदान करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। संगठन ने एक विस्तृत मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी है, ताकि उत्सव के दौरान सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गरिमा और पर्यावरणीय संतुलन को अक्षुण्ण रखा जा सके। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन पत्र सौंपकर इन दिशा-निर्देशों को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस जनहितकारी पहल से न केवल समाज में शांति, परस्पर सहयोग और अनुशासन की भावना सुदृढ़ होगी, बल्कि पर्व की पवित्रता भी बनी रहेगी। मामले में उपमुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख प्रकट किया है।

प्रमुख दिशा-निर्देश एवं कड़े कानूनी प्रावधान:

पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध: प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) और प्लास्टिक निर्मित प्रतिमाओं के निर्माण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

दंड का प्रावधान: नियमों का उल्लंघन करने वाले



विक्रेताओं पर संबंधित नगर निगम अथवा नगर पालिका द्वारा 10,000 से 50,000 तक का अर्थदंड रोपित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब मूर्तियों के निस्तारण का व्यय भी दोषी विक्रेताओं से ही वसूला जाएगा।

इको-फ्रेंडली विकल्प: बाजार में केवल प्राकृतिक मिट्टी, पारंपरिक शिल्पकला और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों से निर्मित मूर्तियों के विक्रय की ही अनुमति होगी।

नशा-मुक्त प्रवेश: किसी भी व्यक्ति को नशे की अवस्था में पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

यूपी में महिलाओं को रिझाने में जुटे राजनीतिक दल

राहिल नोरा चोपड़ा

2027 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। बुधवार को अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने सत्ता में आने पर ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ के तहत सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों के लिए लैपटॉप और महिलाओं के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा का भी वादा किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की और मेधावी स्नातक लड़कियों के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के क्रियान्वयन को दोहराया। भाजपा एक अलग दृष्टिकोण अपना रही है। उसका प्रयास सरकार द्वारा पहले से दी गई कल्याणकारी योजनाओं और उनके आसपास बने भरोसे पर आधारित है। पार्टी दांव लगा रही है कि जिन महिलाओं को पहले ही लाभ मिल चुका है, वे फिर से उसका समर्थन करने की अधिक संभावना रखेंगी। योगी का सबसे बड़ा सेलिंग प्वाइंट सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था को संभालना है। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वापसी को भी उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के साथ भाजपा के भाषण कौशल और जमीनी जुड़ाव को सशक्त बनाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को कोशिश करेगी। इस बीच, भाजपा के लिए 2022 में महिलाओं के बीच बनाई गई बहुत को बनाए रखना योगी के रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सपा के लिए, एक दशक तक विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में लौटने के अपने प्रयास के लिए इन मतदाताओं के बीच सेंध लगाना आवश्यक है। खरगे ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अध्यास पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया और लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखने की मांग की। पार्टी 2029 के लोकसभा चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किए जाने की भी उम्मीद कर रही है। इस मुद्दे पर 45 दिनों से कम समय में खरगे का यह दूसरा पत्र तब आया जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को दावा किया कि एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या यह मानसून सत्र के सत्रावसान में हो रही लगातार देरी का कारण था। मार्च-अप्रैल में पत्रों की एक शृंखला के बाद, खरगे ने 16 जुलाई को मोदी के सामने इस मांग को दोहराया था। उमर पर मंत्रिपरिषद के विस्तार का दबाव: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एन.सी.) मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित विस्तार से पहले उमर अब्दुल के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पास एक नए प्रस्ताव के साथ पहुंची है। लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेट्री (जे.के.पी.सी.सी.) के अध्यक्ष तारिक हमीद करी ने राज्य का दर्जा बहाल होने तक उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। कांग्रेस एन.सी. सरकार का समर्थन करती है लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, जम्मू और कश्मीर में अपने मंत्रिपरिषद के आकार पर एक वैधानिक सीमा है। हालाँकि, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले अब 6 मंत्री शामिल हैं।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

शब्दकोश

अग्निपुराण के अध्याय 360 से 366 तक शब्दकोश है, जिसके पढ़ने से प्रतीत होता है कि प्रसिद्ध कोशकार अमरसिंह ने अपने कोश की रचना में उक्त ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता ली है। कदाचित् वादी भद्र न पश्यति न्याय के अनुसार कोई यह अड़झा लगाये कि- अमरकोश ग्रंथ के पश्चात् उक्त पुराणों की रचना हुई है, और उसके श्लोक ही पुराण-कार ने अपनाये हैं- तो हम उसके उत्तर में यह कहेंगे कि अमरकोश की विद्यमानता में उसके कुछ पद्य अपने ग्रन्थ में लिख लेने से सिवाय कागज काले करने के और क्या फल हो सकता था! हम विशेषतया ऐसे महापुरुषों के लिये जो कि अपने ग्रन्थ में मौलिक विषय लिखने की अद्वितीय योग्यता रखता हो ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते। संस्कृत ग्रन्थकारों ने किसी दूसरे कवि के शब्द अर्थ और भाव आदि का



चुराना तेऽन्यैर्वान्तं समश्नन्ति के अनुसार अतिवृणक्ति कार्य बताया है, अतः अमरकोश के श्लोकों को अग्निपुराणकार ने उद्धृत किया हो यह असम्भव है। हाँ! अमरसिंह अपने ग्रन्थ का गौरव बढ़ाने के लिए आर्ष ग्रन्थों से उचित उद्धरण अवश्य ले सकता है क्योंकि अन्यान्य कवियों ने भी अपने ग्रन्थ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। जैसे कविकुलगुरु कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य के आरम्भमें ही अथवा कृत-वाग्दारे कहकर वाल्मीकि जी की उक्तियों को अपना लक्ष्य बताया है। इस तरह पुराणों में शब्दकोश का भी समावेश विद्यम्मान है।

निरुक्त-शास्त्र

वेदाधं परिज्ञान के लिए निरुक्त का ज्ञानना आवश्यक है, इसीलिए इस शास्त्र को वेदाङ्गों में परिगणित किया गया है। इस समय इस विषय का यास्कनुनिर्कृत निरुक्त एकमात्र ग्रन्थ मिलता है।

क्रमशः ...

ज्ञान/मीमांसा

जातिगत जनगणना संबंधी कांग्रेस-भाजपा के सियासी दांव-पेच

कमलेश पांडे

जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ मौजूदा हमला केवल जाति गिनी जाए या नहीं का सवाल नहीं है, बल्कि असली लड़ाई अब 'डेटा की विश्वसनीयता, सामाजिक न्याय की राजनीति और उससे बनने वाले नए राजनीतिक समीकरण की है। यही वजह है कि अगस्त 2026 में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा जाति-जनगणना पद्धति पर आपत्ति जताई है। इसलिए जातिगत जनगणना सम्बन्धी कांग्रेस-भाजपा के सियासी दांव-पेंचों को ऐसे जानिए।

कांग्रेस का तर्क है कि यदि जातियों के नाम दर्ज करने के लिए स्पष्ट, पूर्व-निर्धारित सूची/कोडिंग व्यवस्था नहीं होगी, तो अलग-अलग नाम, वर्तनी और उपजातियों के कारण आंकड़े अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसलिए उसने इसे दुरुस्त करने की मांग उठाई, ताकि जातिगत जनगणना सही तरह से हो सके। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस ने 2011 में जिस जातिगत जनगणना के आंकड़ों को छुपाने में ही अपनी भलाई समझी थी, उसी ने अब भाजपा पर दबाव बना दिया कि जातिगत जनगणना करवाओ और भाजपा को यह बात माननी पड़ी, क्योंकि लालू-नीतीश की समझदारी के सामने भाजपा नेतृत्व विवश हो गया।

चाहे लालू प्रसाद हों या नीतीश कुमार, इन्होंने सबके लिए कम और अपनी जातियाँ और उससे पहले दोस्तों के लिए बहुत कुछ सोचा। इसलिए 'डेढ़-दो दशक में खरगे का यह दूसरा पत्र तब आया जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को दावा किया कि एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या यह मानसून सत्र के सत्रावसान में हो रही लगातार देरी का कारण था। मार्च-अप्रैल में पत्रों की एक शृंखला के बाद, खरगे ने 16 जुलाई को मोदी के सामने इस मांग को दोहराया था। उमर पर मंत्रिपरिषद के विस्तार का दबाव: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एन.सी.) मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित विस्तार से पहले उमर अब्दुल के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पास एक नए प्रस्ताव के साथ पहुंची है। लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेट्री (जे.के.पी.सी.सी.) के अध्यक्ष तारिक हमीद करी ने राज्य का दर्जा बहाल होने तक उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। कांग्रेस एन.सी. सरकार का समर्थन करती है लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, जम्मू और कश्मीर में अपने मंत्रिपरिषद के आकार पर एक वैधानिक सीमा है। हालाँकि, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले अब 6 मंत्री शामिल हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि जाति जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का कॉलम नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आंकड़े जुटाने के सरकारी तरीकों पर भी अंगुली उठाई और कहा कि जाति जनगणना में जाति का कॉलम खुला रखकर एक सवाल छोड़ दिया गया है, यानी यहां सभी को अपनी जाति खुद लिखनी



है। अब चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही जाति को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, तो आंकड़े उलझे हुए मिल सकते हैं। इससे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होगा।

वाकई, इस आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना में भी इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया था। तब 46 लाख से ज्यादा जातियां, उपजातियां, उपनाम दर्ज हो गए थे। इन आंकड़ों में इतनी विसंगति थी कि सरकार ने इनको जारी ही नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का ताजा सुझाव है कि लोगों पर छोड़ने के बजाय जातियों की पहले से एक तय सूची/लिस्ट होनी चाहिए। इससे एक जाति एक ही नाम से दर्ज होगी और स्पेलिंग की भी गलती नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं है कि देश में कितनी जातियां और उनकी कितनी आबादी है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों की वास्तविक स्थिति क्या है। अबतक असमानता दूर करने के लिए लागू की गई नीतियां किन्हीं कारगर रहीं और आगे उनमें किन बदलावों की दरकार है, इसकी सही तस्वीर जानने के लिए आंकड़ों की शुद्धता मायने रखती है। इसी से शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। और अगर किसी तरह का सवाल या संदेह है, तो उसे पहले ही दूर कर लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी सुझाव आते हैं, उन पर विचार-विमर्श करने में हर्ज नहीं है। साथ ही, यह भी स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है कि जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा।

चूंकि जाति जनगणना का देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ने वाला है। इसलिए प्रक्रिया पूरी तरह भरोसेमंद और सवालों के परे होनी चाहिए। अब आइए सबसे पहले इस जातिगत जनगणना के लाभ-हानि को समझने की कोशिश करते हैं।

पहला, नीति पहली बार वास्तविक

सामाजिक आंकड़ों पर टिक सकती है। किस जाति की कितनी आबादी है, उसकी शिक्षा, रोजगार, आय और सरकारी योजनाओं तक पहुंच कैसी है—इसका बेहतर आधार मिल सकता है। इससे कल्याणकारी योजनाओं को अधिक लक्षित किया जा सकता है।

दूसरा, आरक्षण पर बहस अधिक तथ्य आधारित हो सकती है। अभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वास्तविक जनसंख्या को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। इसलिए विश्वसनीय आंकड़े मिलने पर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की समीक्षा का आधार मजबूत हो सकता है।

तीसरा, जिसकी जितनी संख्या... राजनीति को आंकड़ों की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस अलग-अलग अनुमान हैं। इसलिए विश्वसनीय आंकड़े मिलने पर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की समीक्षा का आधार मजबूत हो सकता है।

तीसरा, जिसकी जितनी संख्या... राजनीति को आंकड़ों की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस अलग-अलग अनुमान हैं। इसलिए विश्वसनीय आंकड़े मिलने पर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की समीक्षा का आधार मजबूत हो सकता है।

तीसरा, जिसकी जितनी संख्या... राजनीति को आंकड़ों की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस अलग-अलग अनुमान हैं। इसलिए विश्वसनीय आंकड़े मिलने पर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की समीक्षा का आधार मजबूत हो सकता है।

दूसरी बड़ी समस्या डेटा की गुणवत्ता है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं; एक ही समुदाय के अलग-अलग स्थानीय नाम और वर्तनी हैं। 2011 के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आंकड़ों में ऐसी तकनीकी समस्याओं का हवाला सरकार पहले भी दे चुकी है।

इसलिए कांग्रेस की मौजूदा आपत्ति पूरी तरह खारिज करने लायक भी नहीं है। सवाल यह है कि जाति गिाने के बाद उसे सही ढंग से वर्गीकृत और सत्यापित कैसे किया जाएगा।

यहीं इस विवाद का राजनीतिक अर्थ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि 2024 के बाद कांग्रेस ने जाति जनगणना + सामाजिक न्याय + प्रतिनिधित्व को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। भाजपा ने अप्रैल 2025 में आगामी जनगणना में जाति को शामिल करने का निर्णय लिया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। अर्थात कांग्रेस की पुरानी मांग को स्वीकार करके भाजपा ने कांग्रेस का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अपने हाथ में ले लिया। इसलिए अब कांग्रेस की रणनीति है: जाति जनगणना हुई तो सही, लेकिन ऐसी हो कि



के पुत्र भारद्वाज को भरत का पुत्र स्वीकार कराया। भारद्वाज की प्रेरणा से भरत को वितथ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने के बाद भरत स्वर्गलोक चले गए और भारद्वाज वितथ का राज्याभिषेक कर खुद वन चले गए। वितथ के पांच पुत्र हुए—सुहोत्र, सुहोता, वग, गर्ग और कपिल। इनमें सुहोत्र के वंश में काशिक और गुत्समति थे। गुत्समति के वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का विस्तार हुआ। काशिक के दो पुत्र हुए—काशेय और

दीर्घतपा। सुहोत्र के एक अन्य पुत्र बृहत हुआ, जिससे अजमीढ, द्विमीढ और पुरमीढ का जन्म हुआ। अजमीढ की तीन रानियां नीलिनी, केशिनी और धूमिनी थीं। नीलिनी से सुशांति उत्पन्न हुए। उनके वंश में पुरुजाति और वाह्याश्व का जन्म हुआ। वाह्याश्व के पांच पुत्र मुद्गल, संजय, बृहदिषु, यवीनर और कुमिलाश्व हुए। उनका राज्य पंचाल कहलाया और वे पंचाल नरेश। मुद्गल के वंश में मोदृत्य ऋषि उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र इंद्रसेन हुए, जिनसे वध्रश्च का जन्म हुआ। वध्रश्च और, अप्सरा मेनका से दो संतानें उत्पन्न हुईं-पुत्र दिवोदास और कन्या अहल्या। दिवोदास आगे चलकर महान राजा बने। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। महर्षि गौतम और अहल्या के पुत्र

शतानंद भी अपने माता-पिता के समान महान तपस्वी और विद्वान थे। वह मिथिला के राजा जनक के राजपुरोहित बने। जब महर्षि विश्वामित्र भगवान राम व लक्ष्मण को लेकर जनक की सभा में पहुंचे, तब शतानंद ने ही उनका आदर-सत्कार किया था। उन्होंने श्रीराम को महर्षि विश्वामित्र के महान तप, त्याग और पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया। सीता स्वयंवर के अवसर पर भी वह उपस्थित थे। शतानंद के पुत्र शरद्धान धनुर्वेद के महान आचार्य थे। एक दिन एक अप्सरा को देखकर उनका वीर्य संकटों पर गिर पड़ा, जिससे एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। शरद्धान, दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। उसी समय राजा शांतनु वन में शिवार के लिए निकले थे। वह नवजात बच्चों को अपने महल ले आए और उनका पालन-पोषण किया।

डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई करवट

ललित गर्ग

भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों की तल्खी के बाद अब संवाद, संघम और व्यावहारिक सहयोग का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। इसे किसी अचानक आए परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को साथ लेकर चलने वाली एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इस बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। 25 अगस्त को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने इस प्रक्रिया को ठोस आधार दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा निर्धारण की दिशा में शीघ्र एवं सार्थक प्रगति करने तथा सैन्य-द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। डोभाल की बीजिंग यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल सीमा विवाद पर बातचीत नहीं थी। यह उस व्यापक प्रश्न पर विमर्श था कि क्या भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के बावजूद बस-अस्तित्व, स्थिरता और पारस्परिक हितों का रास्ता तलाश सकते हैं। दोनों देशों ने दो अतिरिक्त सैन्य संपर्क-बिंदु और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में दो अतिरिक्त सैन्य दूरभाष संपर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है। सीमा व्यापार, कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीमा-पार सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है।

अजीत डोभाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुरक्षा और कूटनीति को परस्पर विरोधी नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है-मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था ही प्रभावी कूटनीति की आधारभूमि बन सकती है। चीन के संदर्भ में भी भारत का संदेश यही रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना द्विपक्षीय संबंधों का पूर्ण सामानीकरण संभव नहीं है। 25वें दौर की वार्ता में यही भारतीय दृष्टिकोण प्रमुखता से सामने आया। डोभाल का व्यक्तित्व केवल वार्ताकार का नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीतिकार का है। वे लंबे समय तक खुफिया तंत्र में रहे, विभिन्न



संवेदनशील क्षेत्रों में काम किया और बाद में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख बने। भारत सरकार के अनुसार, उन्होंने पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी कार्यशैली में एक उल्लेखनीय संतुलन दिखाई देता है—जहां आवश्यक हो वहां कठोरता और जहां अवसर हो वहां संवाद। उड़ी के बाद की सर्जिकल कार्रवाई, बालाकोट की कार्रवाई, डोकलाम संकट के दौरान कूटनीतिक प्रयास और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका इसी व्यापक दृष्टिकोण के उदाहरण माने जाते हैं। 2026 में उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया।

भारत-चीन संबंधों का सबसे कठिन दौर वर्ष 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद आया। चार वर्षों तक सीमा पर सैन्य तनाव बना रहा। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सैनिकों की पूर्ण वापसी और संबंधित विवादों के समाधान के बाद संबंधों को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी वर्ष कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकाती में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति तथा मतभेदों को संबंधों की समग्र दिशा को प्रभावित न करने देने पर जोर दिया था। यही वह बिंदु था जहां डोभाल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। दिसंबर 2024 में विशेष

प्रतिनिधि स्तर की बातचीत से शुरू हुई प्रक्रिया अब 25वें दौर तक पहुंची है। इस बार आठ बिंदुओं पर बनी सहमति संकेत देती है कि बातचीत केवल औपचारिकता नहीं रह गई है। सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ तथा कार्य समूहों को सक्रिय करना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलतफहमी रोकने के लिए मौजूदा सैन्य एवं कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग और नए संपर्क तंत्र बनाना व्यावहारिक विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत-चीन संबंध केवल सैनिक चौकियों और राजनयिक बैठकों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संपर्क भी रहा है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली और विस्तार, सीमा व्यापार मार्गों को फिर खोलना तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। 2026 में कैलाश-मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथू ला, दोनों मार्गों से संचालित हुई है। 25वें दौर की वार्ता में तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर खोलने की प्रगति का स्वागत किया गया तथा व्यापार और तीर्थयात्रा को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह छोटा कदम नहीं है। सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाना एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के लिए व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना दीर्घकालिक शांति की सामाजिक नींव तैयार करता है।

शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा एक अवसर भी है, परीक्षा भी है। इसी पृष्ठभूमि में 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है। यदि यह यात्रा होती है तो यह सात वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके साथ लगभग चार सौ अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। हालांकि 27 अगस्त तक चीन की ओर से उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए शी की

संभावित यात्रा को केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी नहीं माना जाना चाहिए। यह भारत-चीन संबंधों की वास्तविक दिशा को परखने का अवसर हो सकती है। वर्ष 2019 का चेन्नई संवाद अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण वार्तावरण में हुआ था, लेकिन उसके एक वर्ष बाद गलवान ने संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया। अब यदि शी नई दिल्ली आते हैं तो दोनों देशों के पास उस टूटे हुए विश्वास को सावधानी से जोड़ने का अवसर होगा। लेकिन भारत को उत्साह में अपनी मूल सुरक्षा चिंताओं को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, सीमा निर्धारण का लंबित प्रश्न और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पारदर्शिता जैसी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए भारत की नीति मित्रता की आकांक्षा, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होनी चाहिए।

डोभाल की विशेषता यही है कि वे संवाद को कमजोरी नहीं बनने देते और शक्ति को टकराव का पर्याय भी नहीं बनाते। उनकी कूटनीति में संदेश स्पष्ट है-भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा कीमत पर नहीं, सहयोग चाहता है, लेकिन समानता के आधार परय संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सीमा की वास्तविकताओं को भुलाकर नहीं। आज भारत-चीन संबंध जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां डोभाल की भूमिका संकटमोचक से आगे बढ़कर विश्वास-निर्माता और सुरक्षा-आधारित कूटनीति के सूत्रधार की बनती दिखाई देती है। 25वें दौर की वार्ता में हुई आठ सूत्रीय सहमति इसका प्रमाण है कि कठिनतम मतभेदों के बीच भी संवाद के रास्ते खुले रखे जा सकते हैं। शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा इस प्रक्रिया को शीर्ष नेतृत्व की राजनीतिक दिशा दे सकती है। किंतु असली सफलता किसी एक शिखर बैठक की तस्वीर में नहीं, बल्कि सीमा पर स्थानी शांति, पारस्परिक विश्वास, व्यापारिक संपर्क और विवादों के न्यायसंगत समाधान में होगी। भारत को चीन से संबंध सुधारने हैं, लेकिन अपनी सामरिक स्वायत्तता और सुरक्षा-सजगता के साथ। डोभाल की कूटनीति का सार भी यही है—संवाद के दरवाजे खुले रहें।

आज का इतिहास

- 1559 महान सम्राट अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर का जन्म हुआ।
- 1659 दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फाँसी दी गयी।
- 1682 विलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कोलोनो की स्थापना की।
- 1780 जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया।
- 1806 न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र ‘डेली एडवर्टाइजर’ आखिरी बार प्रकाशित किया गया।
- 1928 द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना।
- 1947 भारतीय संविधान का प्राारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया।
- 1951 फिलीपींस और अमेरिका ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 1984 अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ ने पहली बार उड़ान भरी।
- 1991 अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1999 पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न।
- 1999 पूर्वी तिमोर के निवासियों ने इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया।
- 1999 संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को परिणाम की घोषणा की।
- 2002 ताइवान में भूकम्प के झटके महसूस किये गए।
- 2002 कोनोको इंक और फिलिप्स पेट्रोलियम ने विलय कर कोनोकोफिलिप्स बनायी।
- 2002 यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी।
- 2003 रूसी पनडुब्बी बरेट्स सागर में डूबी, नौ परे, आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता।
- 2003 समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
- 2007 जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमत्ज़र और आल्फ़ोंस स्टालहोफ़ेन ने अल्टरट् आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को ग़ुलत ठहराने का दावा किया। नेपाल की कोईराला सरकार ने चार माओवादी विद्रोहियों को फ्रांस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और मलेशिया का राजदूत नियुक्त किया। बांग्लादेश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।
- 2008 बिड़ला परिवार के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला का निधन हुआ।
- 2014 दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री टॉम थबाने सेना द्वारा कथित तौर पर तख्तापलट के प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गये।

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

ललित गर्ग

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारों और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नाँव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024–25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करारी आंकड़े लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं।

विर्दबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार को विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए।

निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024–25 में कुल 14.71



लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023–24 के 1,10,971 से घटकर 2024–25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है।

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014–15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024–25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की

बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है।

इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और

अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है।

यहां एक कठोर लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार होना चाहिए-क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित अथवा अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब नीति बनाने वाले परिवार स्वयं उसी व्यवस्था का अनुभव करेंगे, तब शायद स्कूल की टूटी छिड़की, बंद शौचालय, शिक्षक की कमी और खराब मिड-डे-मील केवल फाइल की टिप्पणी नहीं रहेंगे, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएंगे। शिक्षा को केवल मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म या पुस्तक पुस्तकों की योजनाओं तक सीमित नहीं किया जा

सकता। ये आवश्यक हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना नहीं, उसे ज्ञान, विवेक, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास से संपन्न नागरिक बनाना है। जिस बच्चे को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे कल विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

सरकार को अब घोषणाओं से आगे बढ़कर ‘राष्ट्रीय सरकारी स्कूल कायाकल्प मिशन’ जैसी व्यापक पहल पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल के लिए शिक्षक उपलब्धता, भवन की सुरक्षा, पेयजल, बिजली, डिजिटल सुविधा, शौचालय, पुस्तकालय, खेल मैदान और सीखने के परिणामों के स्पष्ट मानक तय हों। हर स्कूल का सार्वजनिक डैशबोर्ड हो और हर वर्ष यह बताया जाए कि कितने बच्चे पढ़ना, लिखना और गणित करना सीख पाए। शिक्षक नियुक्ति में पारदर्शिता हो और राजनीतिक हस्तक्षेप पर कठोर अंकुश लगे। स्कूल प्रबंधन समितियों को वास्तविक अधिकार दिए जाएं तथा जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सबसे जरूरी है कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठाया जाए। सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि सरकारी स्कूल किसी पार्टी के नहीं, भारत के भविष्य के स्कूल हैं। यदि किसी राजनीतिक दल को स्कूलों की बदहाली दिखाई देती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मुद्दा राजनीतिक श्रेय का नहीं, बच्चों के भविष्य का होना चाहिए।

महाराष्ट्र महायुति गठबंधन: मराठी मानुस के लिए तैयार होती नई चुनौती

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरवार को राज्य के ऑटो-रिक्षा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने की अवधि एक साल बढ़ा दी। हालांकि इस पर महागठबंधन सरकार के दल शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक ने सख्ती की थी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुप्पी साधे थी, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंजने पर राज्य का विधानसभा चुनाव समीप दिखा और मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का फैसला किसी बहाने टाल दिया। प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है कि फडणवीस से मिले चालकों के एक शिष्टमंडल से चर्चा के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। परंतु अंदर की बात किसी से छिपी नहीं थी। दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे) के दबाव में शिवसेना के नए कदम से एक अवधि में गैर मराठी ऑटो-टैक्सी चालकों का ही लाभ था। वैसे भी उनके यात्रियों की संख्या में दूसरे भाषा-भाषी अधिक हैं। यदि मराठी में भी ठीक-ठाक हो जाते हैं तो वे राज्य के चालकों के लिए चुनौती बन जाएंगे। उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में अनेक ऐसे उदाहरण सामने हैं। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक गैर मराठी भाषी उच्छृङ्खल कार्य कर रहे हैं। यद्यपि अनेक मराठी भाषी भी काफी समय से दूसरी भाषाओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 12 लाख 96 हजार से ज्यादा ऑटो हैं, जबकि करीब पांच लाख टैक्सियां हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रेटर मुंबई में करीब पांच लाख टैक्सियां और ऑटो-रिक्षा पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 75 प्रतिशत ऑटो-टैक्सी चालक गैर मराठी और हिंदीभाषी इलाकों से आए हुए हैं। राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या

में ऑटो-टैक्सी चालक हिंदीभाषी या मुस्लिम हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे महानगरों में केवल मराठी समझने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में संभव है, किंतु वहां ऑटो-टैक्सी चालक नाम मात्र के हैं और आम तौर पर वे स्थानीय मराठीभाषी ही होते हैं। शहरी क्षेत्र में हिंदी-अंग्रेजी की जानकारी अपेक्षित होती है, जिसे संवाद की भाषा के रूप में हिंदी पूरा कर लेती है। यह सुविधा हिंदी-मराठी दोनों भाषाओं को बोलने वाले चालकों के लिए होती है। वे उसका अच्छी तरह से लाभ लेते हैं। समस्या तब आती है, जब यात्री हिंदी नहीं समझता और केवल मराठी ही जानता है। उस स्थिति में स्थानीय चालकों के लिए लाभ की स्थिति बन जाती है। यदि उसे भी हाथ से निकल जाने दिया जाएगा तो भूमिपुत्रों के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ लगातार बढ़ा होता नजर आएगा। महाराष्ट्र में देखा गया है कि सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग स्थानीय भाषा जल्दी अपना लेते हैं। वे स्थानीय भाषा के कामचलाऊ ज्ञान से अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसी प्रकार उद्योग और बाजार में सुविधा अनुसार भाषा का उपयोग हर कोई कर लेता है। वहां सरकार का कोई बंधन नहीं है और न ही कोई नियम-कानून लागू है। कुछ अंग्रेजी बोर्ड को लेकर आपत्ति उठी थी। कमोबेश वह हर जगह दूर हो गई है। किंतु केवल भाषा के मामूली ज्ञान से बाहरी राज्य के व्यवसायियों की स्पर्धा तैयार हो गई। राजस्थानी, गुजराती, सिंधी समाज पहले ही मराठी मन के साथ रच-बस चुके थे। अब अन्य हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए व्यवसाय का रास्ता खुलता जा रहा है। बताया जाता है कि दक्षिण के राज्यों में भाषाई अस्मिता बहुत अधिक है, इसलिए वहां दूसरी भाषा को अवसर नहीं मिलता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है।

विरोध प्रदर्शन करें पर ना हो सीमाओं का अतिक्रमण

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आये दिन होने वाले प्रदर्शनों के चलते सामान्य जनजीवन को बंधक बना देने की प्रवृति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदर्शनों के कारण कई बार तो जीवन मरण तक के हालात पैदा हो जाते हैं। अन्य सब कारणों और परिणामों को थोड़ी देर के लिए अलग कर भी दिया जाए तो भी हालात यहां तक हो जाते हैं कि यातायात प्रभावित होने से तत्काल मेडिकल रिलिफ की आवश्यकता वाले बीमारों तक का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने, अपनी बात रखने और अपना विरोध आंकित कराने का सबको अधिकार है। केई गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए पर इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात कहने के चक्कर में दूसरों को अपने सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित कर दें। विरोध प्रदर्शन के साथ ही साथ दायित्व भी होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विरोध भी नहीं होता पर कब इस तरह के प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और कानून व्यवस्था के गंभीर हालात हो जाते हैं इसका खामियाजा प्रदर्शनकारियों को नहीं अपितु प्रशासन और आमजन को भुगताना पड़ता है। सीजीपी के हालिया प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में जो हालात बने और जयपुर में पिछले दिनों सीजीपी द्वारा स्कूल प्रकरण को लेकर ग्रामवासियों और सीजीपी लोगों के साथ हालात बने यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। रांची और देश के अन्य स्थानों के प्रदर्शनों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। शहर की सामान्य व्यवस्था को ही प्रभावित करने वाले स्थानों पर प्रदर्शन स्वीकृति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति अमित महानजन की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शहर के बीच प्रदर्शनों की अनुमति क्यों कर दी जानी चाहिए। दरअसल सीजीपी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किये गये और यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन और पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल जाता है पर मूल कारण को नजरअंदाज कर दिया जाता



है। इससे पहले 2017–18 में जलकटू घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति राजेश्वरन आयोग की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

लोकतंत्र में विरोध अधिकार हो सकता है पर विरोध का एक तरीका होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सबको अधिकार है पर अपने विरोध प्रदर्शन के चक्कर में अन्य और वह भी आमनागरिकों का जनजीवन प्रभावित करने का किसी को अधिकार नहीं हो सकता। विरोध के चलते कानून हाथ में लेना या क्षेत्राधिकार से बाहर जाना एक सभ्य समाज और सभ्य नागरिक की पहचान नहीं हो सकती। सरकारी या निजी संपत्ती को नुकसान पहुंचाना या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। एक बात यह भी समझनी होगी कि पुलिस प्रशासन भी आखिर आदमी है और देखा जाए तो उनका मरण दोनों तरफ से हो जाता है। यदि प्रदर्शनकारियों को एक सीमा से अधिक बढ़ने पर रोके नहीं तो प्रशासन की विफलता कहने में कोई देरी नहीं लगाता, यहां तक कि प्रशासन की इंटेलिजेंस फैलियर जैसे आरोप लग जाते हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की आलोचना आम हो जाती है पर जब कई बार प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान बेरिफेड तोड़ने, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और निरपराध आमजन को निशाने पर लेने लगते हैं तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि फिर प्रशासन गुलाब के फूल देकर तो प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं कर सकता हालांकि प्रशासन को भी संयम बरतते हुए ही कदम उठाने चाहिए।

दरअसल तस्वीर के दोनों पक्षों को देखना होगा। यदि प्रदर्शन सामान्य होता है और अनुमति प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो उस पर पुलिस प्रशासन की सख्ती को किसी भी हालात में स्वीकारा नहीं जा सकता पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है तो उस पर प्रशासन को भी कानूनी दायर्य में रहते हुए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी।

अब जयपुर के स्कूल की घटना का विश्लेषण करें तो हालात की ओर ध्यान दिलाना एक उचित कदम हो सकता है पर स्कूल या किसी भी सरकारी-गैरसरकारी संस्थान का निरीक्षण का अधिकार किस कानून ने दे दिया है। एक सीमा तक प्रदर्शन आपका अधिकार हो सकता है पर प्रदर्शन से माहौल को तनावपूर्ण और द्वेषतापूर्ण बनाने की किसी भी व्यवस्था में अनुमति नहीं दी जा सकती और नहीं दी भी जानी चाहिए। प्रशासन, प्रदर्शनकारियों और आमजन को अपनी सीमाओं को समझना होगा। सुर्खियों में बनने के लिए कदम उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

क्या कभी सोचा है कि हमारे प्रदर्शन से प्रदर्शन वाले शहरवासियों को कितना प्रभावित करता है। प्रदर्शन वाले शहर का कहीं ज्यादा तो कहीं कम यातायात प्रभावित हो जाता है। निजी व सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है। मरीजों व जरूरी काम वालों को बीच रास्ते अटकना पड़ जाता है। नौकरपेशा या धंधे पर जाने वाले रास्ते में ही अटक जाते हैं।

दैनिक काम के आधार पर रोजी रोटी कमाने वालों की मजदूरी अटक जाती है। शहर की सभी तरह की सप्लाई चैन बाधित हो जाती है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यस्त हो जाता है तो लोगों में असुरक्षा की भावना बनती है और बाहर निकलने से पहले सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और अब तो प्रशासन द्वारा ऐसे शहरों में इंस्टेंटर बंद करने तक का निर्णय कर लिया जाता है जिससे सामान्य गतिविधियां, बैंकिंग व्यवस्था, सूचनाओं का आदान-प्रदान और पढ़ाई-लिखाई तक पर असर पड़ता है। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महानजन की यह टिप्पणी कि शहर को बेवजह बंधक बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है।

जादवपुर विवि में आजादी के नारे लगाने वालों पर भड़के शुभेंदु

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल का जादवपुर विश्वविद्यालय एक समय देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था, लेकिन आज कैंपस से ज्ञान, शोध और अकादमिक विमर्श की बजाय ‘आजादी’ के नारे और विवादित राजनीतिक गतिविधियों की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। यहां सवाल उस मानसिकता का है जो भारत में रहते हुए भारत से ही ‘आजादी’ की मांग करने तक पहुंच जाती है। देखा जाए तो ‘कश्मीर मांगे आजादी’ जैसे उद्घोष और माओवादी नेता किशनजी के समर्थन में लिखे नारों ने एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर विश्वविद्यालय के भीतर किस तरह की राजनीति और किस तरह की मानसिकता को जगह दी जा रही है?

ऐसे लोगों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का खूब बिल्कुल स्पष्ट और सख्त है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि वे इस ‘बीमारी’ को जानते हैं और इसकी ‘दवा और इलाज’ भी जानते हैं।

देखा जाए तो जादवपुर की घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि विश्वविद्यालयों की वैचारिक स्वतंत्रता का केंद्र बनाए रखा जाए या ऐसी राजनीति का अखाड़ा बनने दिया जाए, जो धीरे-धीरे पूरे अकादमिक माहौल को विषाक्त कर देती है।

यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ‘आजादी’ शब्द अपने आप में समस्या नहीं है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति जताने और सरकार की आलोचना करना अधिकार है। लेकिन जब ‘आजादी’ का नारा भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाने वाले नारों के साथ जुड़ता है, तब उस महज छात्र राजनीति या वैचारिक असहमति कहकर टाल देना भी उचित नहीं होगा। जादवपुर में उठे नारों के संदर्भ में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर किससे और किस चीज से आजादी मांगी जा रही है?

शुभेंदु अधिकारी ने इसी सवाल को बेहद तीखे अंदाज



में उठाया है। विश्वविद्यालय के बाहर करीब दस हजार लोगों की मौजूदगी में ‘वंदे मातरम्’ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा परिसरों में इस तरह के नारे बंद होने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जिस आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, मार्तीण्डी हाजरा और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उस आजादी को हासिल किए दशकों बीत चुके हैं।

शुभेंदु अधिकारी के इस कड़े रुख की तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने उस असहज सवाल को उठाने का साहस किया है जिसे अक्सर राजनीतिक शुद्धता के नाम पर दबा दिया जाता है। विश्वविद्यालय विचारों की प्रयोगशाला हो सकता है, लेकिन वह राष्ट्र-विरोधी हिंसक विचारधाराओं का सुरक्षित अड्डा नहीं बन सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की अखंडता को चुनौती देने के बीच एक स्पष्ट रेखा है। उस रेखा को जानबूझकर धुंधला करना लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं, बल्कि उनका दुरुपयोग है।

सबसे चिंता की बात यह है कि जादवपुर की घटना को अलग-थलग घटना मानकर छोड़ देना वास्तविक समस्या से आंखें मूंदना होगा। देश के कई विश्वविद्यालयों में पिछले वर्षों में ऐसे नारे और ऐसी राजनीति कैंपस के अकादमिक वातावरण पर भारी पड़ी है। जेएनयू हो, हैदराबाद विश्वविद्यालय हो या दूसरे परिसरों में उभरे अतिवादी छात्र

राजनीतिक संघर्ष हों, जब विश्वविद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा पहचान की राजनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण, हिंसक टकराव और उकसाऊ नारों को महत्व मिलने लगता है तो अंततः सबसे बड़ा नुकसान छात्रों की शिक्षा और संस्थान की प्रतिष्ठा को होता है। जादवपुर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने इसी संदर्भ में जेएनयू और उस्मानिया विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कैंपस को ‘सुधारने’ की बात कही है। यहां एक और सवाल पूछा जाना चाहिए। जो लोग हर मुद्दे पर ‘आजादी’ का नारा लगाते हैं, क्या वे देश के संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को भी उसी गंभीरता से स्वीकार करते हैं? क्या उन्हें उन सैनिकों की चिंता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं? क्या उन्हें उन नागरिकों की चिंता है जो आतंकवाद का शिकार होते हैं? और यदि उनकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो वह लड़ाई विश्वविद्यालय की कक्षाओं, शोध और लोकतांत्रिक बहस के जरिए क्यों नहीं लड़ी जाती?

बेशक, सरकार या मुख्यमंत्री को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वैध असहमति को दबाया न जाए। किसी छात्र को केवल विचार रखने के कारण देशद्रोही करार देना भी लोकतांत्रिक रास्ता नहीं है। लेकिन यही सिद्धांत दूसरी तरफ भी लागू होना चाहिए कि विचारधारा के नाम पर देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले नारों को भी ‘छात्र अधिकार’ का कवच नहीं मिल सकता।

देखा जाए तो जादवपुर का सवाल इसलिए सिर्फ एक विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है। यह उस दिशा का सवाल है जिसमें देश के विश्वविद्यालय आगे बढ़ेंगे। क्या वे ज्ञान, शोध, तर्क और राष्ट्रनिर्माण के केंद्र बनेंगे या राजनीतिक कट्टरता के अखाड़े? शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम इस बहस को सामने लाने का काम किया है। अब जरूरत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी साफ करे कि कैंपस में विचारों की आजादी होगी, लेकिन हिंसा, धमकी और देश की अखंडता के खिलाफ उकसावे के लिए कोई आजादी नहीं होगी।

दिमागी नक्सली मतलब ‘गैर-भारतीय’ बौद्धिक वर्ग

एस प्रसन्नराजन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने अनौपचारिक और सटीक अंदाज में बात करने की कला में महारत हासिल की है। वह तथ्यों के साथ खेल सकते हैं और सच को जरूरी बहस का मुद्दा बना सकते हैं। हालांकि, उनके शब्द ‘covefele’ का मतलब मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में नहीं मिलता। ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर बातचीत के मामले में ओबामा से बिल्कुल उलट हैं; उनकी बातचीत तेज-तर्रार, संक्षिप्त और बोलचाल की भाषा वाली होती है। इसे राष्ट्रपति की भाषा में ‘मामा गिनिमलिज्म’ (कम से कम शब्दों में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात कहना) कह सकते हैं। किसी भी स्थिति को विचारों या भाषा की जटिलता के साथ पेश नहीं किया जाता, और तारीफ या बुराई को बस चार शब्दों में समेट दिया जाता है- अच्छा, बुरा, सुंदर और भयानक। सोशल मीडिया के दौर में कम शब्दों में प्रभावी बात कहना समझदारी है। पर, ट्रंप ने कई बार बिना ज्यादा सोचे-समझे बेहद कम शब्दों में ऐसी बातें कहीं, जो बहुत साधारण या सतही हैं। फिर भी, ट्रंप को इसके लिए कोई श्रेय नहीं मिला। लोग अब रूपकों और मुहावरों के बजाय सीधी और साफ भाषा में किए गए आमजन को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय, आक्रामक तरीके से बोलने वाले लोग जल्दी चर्चा में आ जाते हैं। भले ही ऑरवेल ने अपने निबंध पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज में ‘घिसे-पिटे और बेकार वाक्यांशों’ को छोड़ने की बात कही हो। आज नरेंद्र मोदी एक जबर्दस्त वक्ता हैं, जो लोगों के मन में अपनी जगह पक्की करने के लिए हमेशा नए-नए शब्द ढूँढते रहते

हैं। एक शानदार प्रचारक के तौर पर, वह दुश्मन की (चाहे वह देश के अंदर हो या सीमा पार) ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, जो बहुत तीखी और कठोर होती है। उनके कुछ समर्थक उम्मीद करते थे कि सत्ता में आने के बाद भी वह वैसे ही नाटकीय और बड़े कदम उठाएंगे। लेकिन, मोदी ने समझदारी से भाषण और शासन के बीच का फर्क बनाए रखा है। वह सरकार चलाते समय धीरे-धीरे और सोच-समझकर फैसले लेते हैं, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं। स्वतंत्रता दिवस के दिन, उन्होंने दुश्मन को शर्मिंदा करने के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया: ‘दिमागी नक्सल’। इसका मतलब है: ऐसा कट्टर वामपंथी, जो अपनी वैचारिक प्रेरणा क्रांतियों की उन पुरानी किताबों से लेता है, जिन्हें अब भुला दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों वाले नक्सली नहीं, बल्कि ‘दिमाग’ वाले नक्सली हैं। हो सकता है, मोदी सच में मानते हों कि असली विपक्ष इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि वह बौद्धिक वर्ग है, जिसे वह ‘गैर-भारतीय’ मानते हैं। भाषा राजनीतिक हथियारों में से एक है, और ‘नक्सल’ शब्द को बहुत सोच-समझकर चुना गया है, ताकि उस व्यक्ति को अलग-थलग किया जा सके, जिसकी सोच ‘उनके भारत’ से मेल नहीं खाती। फिर, खुद मोदी उन तथाकथित ‘दिमागी नक्सलियों’ के निशाने पर रहते हैं, जो राजनीति का सबसे बुरा संबोधन ‘फासीवादी’ उन लोगों पर उछालते हैं, जो उन्हें बद्रीत नहीं करते। ऐसा करते हुए वे खुद फासीवाद की गंभीरता को कम कर देते हैं। लोगों से अपनी बात मनवाना एक मुश्किल कला है और भाषा हर किसी को इसमें महिर बनने में मदद नहीं करती।

संकष्टी चतुर्थी पर कौन करता है निर्जल व्रत और क्यों

गणेश चतुर्थी कहलाती है पर संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। इस दिन धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्रियां व्रत व गणेश पूजन करती हैं। इस दिन विद्या-बुद्धि-वारिधि, संकट हरण गणेशजी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है।

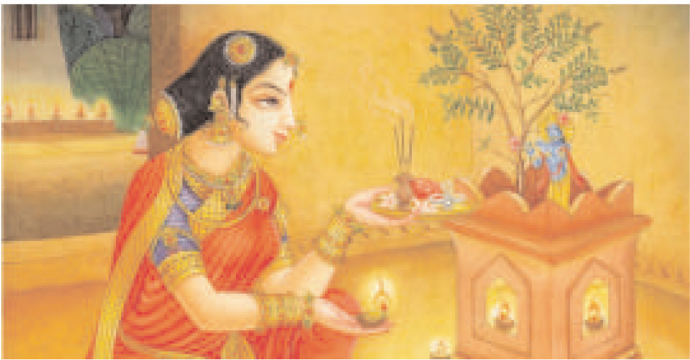


पूजन किया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला तथा प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन कच्चे तिल को कूटकर गणेशजी की मूर्त बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद लोटे में भरा जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं भोजन करती है। संकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड के साथ कूटकर तिलकुटा यानि तिलकुट का पहाड बनाया जाता है। उसको पूजा करके घर का कोई बच्चा

उसकी गर्दन काटता है, फिर सभी को प्रसाद दिया जाता है। तिलकुटे से ही गणेशजी का पूजन किया जाता है तथा इसका ही बायना निकालते हैं और तिलकुट को भोजन के साथ खाते भी हैं। जिस घर में लडके की शादी या लडका हुआ हो, उस वर्ष संकट चौथ को सवा किलो तिलों को सवा किलो शक्कर या गुड के साथ कूटकर इसके तेरह लड्डु बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बहू बायने के रूप में सास को देती है। कहीं-कहीं इस दिन व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। गौरी-गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्षभर उन्हें घर में रखा जाता है। तिल, ईख, गंजी, भांटा, अमरूद, गुड, घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात भर डलिया से ढककर रख दिया जाता है, जिसे 'पहार' कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। उस ठके हुए 'पहार' को पुत्र ही खोलता है तथा उसे भाई-बंधुओं में बांटा जाता है।

घर में अवश्य लगाएं तुलसी के पौधे क्योंकि

- तुलसी एक ऐसा पौधा है। जिसके लाभ अनेकानेक हैं और इसे विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी के कई प्रकार हैं जैसे रक्त तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी, मुख्यरूप से विद्यमान है। तुलसी की इन सभी प्रजातियों के गुण अलग हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने घर का वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं।
- वास्तुदोष दूर करने के लिए इसे दक्षिण-पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी खाली कोने में लगाया जा सकता है।
 - तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बढ़ता है।
 - पूर्व दिशा में यदि खिडकी के पास तुलसी का पौधा रखा जाए तो आपकी संतान आपका कहना मानने लगेगी।
 - अगर संतान बहुत ज्यादा जिदी और अपनी मर्यादा से बाहर है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के तीन पत्ते रोज उसे किसी ना किसी तरह खिला दें।
 - यदि आपकी कन्या का विवाह



तुलसी एक ऐसा पौधा है। जिसके लाभ अनेकानेक हैं और इसे विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी के कई प्रकार हैं जैसे रक्त तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी, मुख्यरूप से विद्यमान।

नहीं हो रहा हो तो तुलसी के पौधे को दक्षिण-पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करें। इस उपाय से जल्द ही योग्य वर की प्राप्ति होगी।

- यदि आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो तुलसी के पौधे को नैऋत्य कोण में रखकर हर शुक्रवार को कच्चा दूध चढ़ाएं।
- नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी हो तो ऑफिस में जहां भी खाली जगह हो वहां पर

सोमवार को तुलसी के सोलह बीज किसी सफेद कपडे में बांधकर कोने में दबा दें। इससे आपके संबंध सुधरने लगेंगे।

- शरीर में नाक, कान वायु, कफ, ज्वर खांसी और दिल की बीमारियों पर तुलसी के पत्ते रोग दूर करने में सहायक हैं।
- तुलसी एकमात्र पौधा है जो जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम है।

कर्म का आधार है विचार

विचारों से ही कर्म का जन्म होता है। वे कर्म की नींव हैं। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, उतने ही श्रेष्ठ हमारे कर्म भी होंगे।आचार्य शिवेंद्र नागर का चिंतन विचारों से ही कर्म का जन्म होता है। वे कर्म की नींव हैं। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, उतने ही श्रेष्ठ हमारे कर्म भी होंगे।

आचार्य शिवेंद्र नागर का चिंतन... वेदांत में बताया गया है कि शारीरिक कर्म मात्र परिणाम है, उसका वास्तविक कारण कुछ और है। शारीरिक कर्म होते हुए दिखता तो है, परंतु वह क्यों किया गया, इसके कारण का पता नहीं चलता। अगर मात्र शरीर ही कर्म कर रहा होता तो देहांत के बाद शरीर

कर्म क्यों करता। मृत्यु के उपरांत शरीर में कर्म करने की क्षमता कुछ देर तक रहती है। मृत व्यक्ति के अंगों का दान करने से वे जीवित व्यक्ति के लिए काम आ जाते हैं। यानी देह में मृत्यु के बाद भी कर्म करने की क्षमता होती है। कार्य करने की प्रक्रिया भले ही शरीर से होती है, लेकिन उसके अन्य कारण हैं। कर्म

का कारण इच्छा है। इच्छा का कारण विचार है तथा विचार का कारण वासना है। वासना का अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। वासना का एक अर्थ 'खुशबू' भी है। स्वभाव या प्रवृत्ति को भी वासना कहा गया है। वासनाएं पहले विचार रूप में प्रकट होती हैं। विचार पर केंद्रित होने पर विचार इच्छा में बदल जाता है। फिर इच्छा कर्म के रूप में प्रकट हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने वासनाओं को 'अज्ञान' कहा है। इसीलिए योगी-महात्माओं ने विचारों की शुद्धता पर बल दिया। विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए, अगर आटे में कंकड़ हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना क्यों न पकाते हों, रोटी खराब ही बनेगी। आटा अच्छा हो, तो रोटी अच्छी भी बन सकती है और खराब भी, परंतु आटा ही खराब हो तो रोटी कैसे अच्छी बनेगी। कर्म का मूल कारण विचार है, इसलिए अगर विचार नकारात्मक होंगे तो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। कर्म अगर भवन है, तो विचार उसकी नींव। कर्म की बुनियाद ही खराब होगी तो भवन अच्छा नहीं होगा। अगर विचारों में स्थिरता है तो कार्य को करने में हमें खुशी का अनुभव होगा। आज के जीवन में तो यह और भी जरूरी है कि किसी काम की शुरुआत अच्छे विचारों से हो।



विविध

भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए पर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही नृसिंह अवतार लिया था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहाद को समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जब प्रहाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया।

भगवान नृसिंह शक्ति के देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु ने 'नृसिंह अवतार' लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया था। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए तथा धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की सदैव संकट आने पर सहायता की।

नृसिंह अवतार भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए पर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही नृसिंह अवतार लिया था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु

ऐसा दानव जिसकी मृत्यु न तो पशु और न ही मनुष्य से हुई



इन मंत्रों का करें उत्तारण
ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्
ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः ।

हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहाद था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु

का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहाद को समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जब प्रहाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त

था, वह प्रहाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखुनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।

ऐसे करें व्रत इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा भगवान नृसिंह की विधी विधान के साथ पूजा-अर्चना करनी चाहिए।

भगवान नृसिंह तथा लक्ष्मीजी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए, तत्पश्चात वेद मंत्रों से इनकी प्राण-प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान नृसिंह की पूजा के लिए फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर रखना चाहिए। गंगाजल, काले तिल, पंच गव्य व हवन सामग्री का पूजन में उपयोग करें। भगवान नृसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नृसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के पश्चात एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से नृसिंह भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन व्रती को सामर्थ्य अनुसार तिल, स्वर्ण तथा वस्त्रादि का दान देना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति लौकिक दुःखों से मुक्त हो जाता है।

यह तो केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है



प्राणों के स्पंदन से ही हमारे भीतर की सभी शक्तियां संचालित होती हैं। स्वामी विवेकानंद का चिंतन... सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह इडा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाडियों द्वारा प्रणशक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। और संपूर्ण शरीर में फैले हुए ज्ञान-तंतुओं द्वारा शरीर की पृथक-पृथक इंद्रियों तक ये नाडियां आदेश पहुंचाती हैं। इडा और पिंगला का व्यवहार करना प्राणायाम का उद्देश्य है। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। श्वासोच्छ्वास द्वारा हवा फेफड़ों में खींचना और उसके द्वारा खून साफकरना, इसमें कोई गुप्त रहस्य नाडियां होती हैं। ये तीनों मेरुदंड के भीतर रहती हैं। बाईं ओर है इडा, दाहिनी ओर पिंगला और बीच में सुषुम्ना। इडा और पिंगला ज्ञान-तंतुओं से बनी हुई हैं, पर सुषुम्ना ज्ञानतंतुमय नहीं है।

प्राणों के स्पंदन से ही हमारे भीतर की सभी शक्तियां संचालित होती हैं। स्वामी विवेकानंद का चिंतन...

सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह इडा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाडियों द्वारा प्रणशक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। और संपूर्ण शरीर में फैले हुए ज्ञान-तंतुओं द्वारा शरीर की पृथक-पृथक इंद्रियों तक ये नाडियां आदेश पहुंचाती हैं। इडा और पिंगला का व्यवहार करना प्राणायाम का उद्देश्य है। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। श्वासोच्छ्वास द्वारा हवा फेफड़ों में खींचना और उसके द्वारा खून साफकरना, इसमें कोई गुप्त रहस्य नाडियां होती हैं। ये तीनों मेरुदंड के भीतर रहती हैं। बाईं ओर है इडा, दाहिनी ओर पिंगला और बीच में सुषुम्ना। इडा और पिंगला की गति जब नियमित होकर अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब हम हुई हैं, पर सुषुम्ना ज्ञानतंतुमय नहीं है।

हैं, प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वत्र दिखाई देने वाली सब क्रियाएं इस प्राण के विभिन्न रूप हैं। यह प्राण सूक्ष्म महाशक्ति है। मस्तिष्क द्वारा यह प्राणशक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। सब वस्तुएं प्राणमय हैं और यह प्राण-शक्ति ही सूर्य, चंद्र, तारे आदि को चला रही है। विश्व में जो कुछ विद्यमान है, वह प्राण के स्पंदन का ही कार्य है। प्राण के सर्वोच्च स्पंदनों का कार्य है- विचार। इससे परे अगर कुछ है, तो वह हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। विभिन्न शक्तियों का रूप लेकर शरीर के प्रत्येक भाग को प्राण ही चलाता है। यह पुरानी कल्पना छोड़ दो कि ईश्वर नाम का कोई है, जो यह सब कार्य चला रहा है। काम करते समय हम श्वक जाते हैं, क्योंकि उसमें प्राणशक्ति व्यय हो जाती है।

भगीरथ ने बदायूं में किया था तप।

जेहन में कौंध जाएंगे। इसके बाद भी शायद संतोषजनक जवाब न मिल सके। इस असमंजस के जवाब को बदायूं आ



गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कहां तपस्या की थी, यह सवाल सुनकर आप भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे। गंगोत्री से गंगासागर तक न जाने कितने तीर्थ चलचित्र की भांति आपके जेहन मे बदायूं, [लोकेश प्रताप सिंह]। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कहां तपस्या की थी, यह सवाल सुनकर आप भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे।

गंगोत्री से गंगासागर तक न जाने कितने तीर्थ चलचित्र की भांति आपके

प्राचीन टीले पर अनूठी गुफा है। कपिल आश्रम के बगल स्थित इस गुफा को भगीरथ गुफा के नाम से जानते हैं। पहले यहां राजा सगर के 60 हजार पुत्रों की भी मूर्तियां थी, जो कुछ साल पहले चोरी चली गई। करीब ही राजा भगीरथ का एक अति जीर्ण-शीर्ण मंदिर है, जहां अब सिर्फ चरण पादुका बची है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुकरखेत (बाराह क्षेत्र) का वैसे भी बहुत महत्व है। बदायूं के कछला गंगा घाट से करीब पांच कोस की दूरी पर कासगंज की ओर बढकर एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, जिस पर लिखा है भगीरथ गुफा। एक गांव है होडलपुर। थोड़ी दूर जंगल के बीच एक प्राचीन टीला दिखाई पड़ता है। बरगद का विशालकाय वृक्ष और अन्य पेड़ों के झुरमुटों बीच मठिया है। इसी टीले पर स्थित है कपिल मुनि आश्रम और भगीरथ गुफा। लाखोरी ईंटों से बनी एक मठिया के द्वार पर हनुमानजी की विशालकाय मूर्ति लगी है। भीतर प्रवेश करने पर एक मूर्ति और दिखाई पड़ती है, इसे स्थानीय लोग कपिल मुनि की मूर्ति बताते हैं। मूर्ति के बगल से ही सुरंगनुमा रास्ता अंदर को जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में प्रवेश कर सकता है। पांच मीटर भीतर तक ही सुरंग की दीवारों पर लाखोरी ईंटें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है कच्ची अंधेरी गुफा। सुरंगनुमा रास्ते से भीतर जाने के बाद एक बड़ी कोठरी मिलती है, जहां एक शिवलिंग भी कोने में है। कोठरी के बाद फिर सुरंग और फिर कोठरी। पर्याप्त रोशनी के साथ इस रास्ते से बढ़ते हुए चौथी कोठरी तक पहुंचने के बाद तो साथ गए स्थानीय फरीदपुर के श्याम गिरि की भी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने सुझाव दिया कि यहां तक भी कोई नहीं आता, बिना ऑक्सीजन मास्क के आगे चलना ठीक नहीं है। श्याम गिरि ने बताया

कि पहले गंगा इसी टीले के बगल से होकर बहती थीं। अभी भी गंगा की एक थारा समीप से होकर बहती है, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। टीले के नीचे स्थित मंदिर से दुर्लभ मुखार बिंदु शिवलिंग भी चोरी चला गया था। इन घटनाओं की बाकायदा प्राथमिकी दर्ज हुई। बाद में पुलिस ने पाली (अलीगढ़) के एक तालाब से शिवलिंग तो बरामद कर लिया, लेकिन सगर पुत्रों की मूर्तियों का अभी भी कोई पता नहीं है। इसी टीले पर तीन समाधि भी हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरिदास की समाधि कहते हैं। यहां राजा भगीरथ का मंदिर है, जो कभी बहुत भव्य था।

कछला बनेगा भगीरथ नगर बदायूं के कछला घाट पर निर्मल गंगा अभिषेकान चला तो गंगासेवी वयोवृद्ध संत त्रिदंडी स्वामी वासुदेवाचार्य ने भगीरथ गुफा के बारे में जानकारी दी। श्री भगीरथ सेवा न्यास ने अभिषेकान से जुड़े कई संगठनों को लेकर कछला घाट पर महाआरती की परंपरा शुरू की तो संतों-धर्माचार्यों ने कछला का नाम भगीरथ नगर करने की मांग उठाई। गौरीशंकर मंदिर के मुख्य आचार्य नारायण दास मुदगल कहते हैं कि इस समय भगीरथ गुफा से सबसे करीब कछला में ही सुविधाजनक गंगा घाट है। इसलिए भी कछला का नाम भगीरथ नगर होना चाहिए और संत-धर्माचार्य खुद यहां राजा भगीरथ का भव्य मंदिर बनवाएंगे। अखिल भारतीय संत सभा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी पगलानंद भी संतों-धर्माचार्यों के साथ बीते सप्ताह भगीरथ गुफा का दर्शन करके आए। नगर पंचायत कछला की चेयरमैन पुष्पा देवी ने बोर्ड की ओर से कछला का नाम भगीरथ नगर किए जाने का प्रस्ताव पारित करवाने का आश्वासन संतों को दिया है।

सोनिया गांधी की किताब छापने से पेंगुइन का इनकार

नई दिल्ली । कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलॉनिंग् अ जर्नी ऑफ लव को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पहले इस किताब को प्रकाशित करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उसने इसे प्रकाशित से इनकार कर दिया है.उसका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी प्रकाशक अलफ्रेड ए नॉफ ने ऐलान किया था कि यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होगी. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने किताब में बदलाव करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रकाशक ने इसे प्रकाशित करने से हाथ खींच लिया. हालांकि, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस दावे को गलत बताया है.पीआरएचआई ने अपने बयान में कहा कि उसने हमेशा यह किताब छापने में दिलचस्पी दिखाई थी और वह इसे छापने के लिए तैयार भी थी. साथ ही यह भी कहा गया कि लेखकों के तथ्यों की जांच करना और उन्हें सुझाव देना प्रकाशन प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होता है।

दिल्ली में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश

नईदिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन समीरा के तहत आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. दोनों पर पाकिस्तान को भारतीय सिम कार्ड भेजने और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारीयां साझा करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ड्रुड्ड से जुड़े एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस मामले में दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले एक पति पत्नी साहिल और समीरा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और उनके लिए काम कर रहे थे. इस ऑपरेशन को स्पेशल सेल ने ऑपरेशन समीरा नाम दिया है. आरोपियों ने भारतीय सिम कार्ड खरीदकर पाकिस्तान भेजे, सेना से जुड़ी जानकारी जुटाई और बदले में पाकिस्तान से पैसे भी लिए।

खनिज संपदा पर झारखंड और केंद्र की जंग

नईदिल्ली । झारखंड की खनिज संपदा से जुड़ा विवाद अब संसद से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद झारखंड सरकार ने केंद्र के संशोधित खान और खनिज कानून, यानी माईस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन 2026 को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य के वित्त और खनन विभाग ने याचिका का कानूनी ब्रूंप्रिंट भी तैयार कर लिया है. राज्य सरकार का कहना है कि नए कानून से झारखंड के आर्थिक हित और राज्यों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे. सरकार के अनुमान के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद झारखंड को हर साल करीब 14 से 15 हजार करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है. सरकार की चिंता है कि इसका असर कई जनकल्याण योजनाओं पर पड़ेगा. इनमें महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली मड़यां सम्मान योजना भी शामिल है।

मणिपुर में भाजपा विधायक के घर पर ग्रेनेड धमाका

नईदिल्ली । मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में एक बीजेपी विधायक के घर पर ग्रेनेड विस्फोट हुआ है. ये धमाका कोंथोजिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. सपम रंजन सिंह के घर पर हुआ. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई. सपम रंजन सिंह हमले से ठीक एक दिन पहले ही नई दिल्ली से लौटे थे. वो दिल्ली में मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने गए थे. धमाके के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 1१30 बजे उनके घर के ठीक पीछे परिसर के अंदर धमाका हुआ. हादसे के बाद दोपहर में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह खुद विधायक सपम रंजन सिंह के आवास पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और सुरक्षा अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली.बीजेपी विधायक सपम रंजन सिंह ने इस धमाके के बाद कहा, %में इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं।

सैफ पर जानलेवा हमला करने वाले शरिफुल ने कुबूला गुनाह

नई दिल्ली । बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू से हमले के मामले में करीब डेढ़ साल बाद बड़ा अपडेट सामने आया है. एक्टर के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर हमला करने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरिफुल इस्लाम ने शुक्रवार को कोर्ट का रुख किया और मामले में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई. आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है. उसके वकील विपुल दुशिंग के मुताबिक, इस्लाम ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है. साथ ही उसने अदालत से नरमी बरतने की अपील भी की है. कोर्ट ने आरोपी को अर्जी पर सरकारी वकील की तरफ से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी.इस मामले में इसी महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख ने मोहम्मद शरिफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अवैध तरीके से घुसने के आरोप लगाए गए हैं।

दुश्मन के टैंकों की खेर नहीं!

अमेरिका से जैवलिन मिसाइल खरीदेगा भारत

नई दिल्ली । भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. भारत अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. उन्होंने इसे भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए बड़ा कदम बताया. साथ ही दोनों देशों के बीच जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम की साथ मिलकर प्रोडक्शन करने की संभावना भी जताई है. जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है. इसे सैनिक कंधे से लॉन्च कर सकते हैं. इसकी खासियत यह है कि इसे अलग-अलग इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है. पहाड़ी इलाकों से लेकर खुले मैदान तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सिस्टम टैंकों और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है. अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत का जैवलिन खरीदने का फैसला दोनों देशों के रक्षा रिश्तों को और मजबूत करेगा. उन्होंने मई 2026 में शांगरी-ला डायलॉग के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री को ओर से कही गई बातों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस सौदे से भारत में जैवलिन



के सह-उत्पादन का रास्ता भी खुल सकता है. भारत लंबे समय से अपनी सेना की एंटी-टैंक क्षमता को मजबूत करने पर काम कर रहा है. ऐसे में जैवलिन सिस्टम की संभावित खरीद को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. खासकर सीमावर्ती इलाकों में टैंक और बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए ऐसे हथियार अहम माने जाते हैं. अमेरिका ने कहा है कि भारतीय सेना ने अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रक्रिया के तहत जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्स्पेरेट्स पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके साथ ही भारत जैवलिन सिस्टम का ग्राहक बन गया है. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और गहरा करता है और भारतीय सेना

के लिए अमेरिकी समर्थन को दिखाता है. जैवलिन एक एडवॉन्स, मीडियम-रेंज, फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों और मजबूत ठिकानों के खिलाफ किया जा सकता है. अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, जैवलिन सिस्टम का निर्माण आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन की ज्वाइंट वेंचर कंपनी करती है. यह सिस्टम अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्पस के अलावा कई दूसरे देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल करती हैं. अमेरिका का कहना है कि इस सौदे से दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच आगे सह-उत्पादन की संभावनाएं खुलेंगी. इससे भारत और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने के लिए नए सहयोग का रास्ता भी तैयार होगा।

नेपाल को लेकर खरगे का पीएम मोदी को पत्र

हमें अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए

नई दिल्ली । नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने नेपाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और नेपाल को मानवीय मदद भेजने की मांग की है।



प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खरगे ने कहा कि वह नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बहुत चिंतित हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब दो हजार लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लोग भोजन, दवा, आश्रय और अन्य जरूरी मदद के लिए परेशान हैं।

खरगे ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मानवीय और राहत सहायता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बाढ़ के कारण नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में कई भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि बचाव और निकासी के प्रयासों को तेज किया जाए और उनकी सुरक्षित और जल्द भारत वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं।

विदेश मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि नेपाल में करीब 320 भारतीय नागरिक अभी भी संपर्क में नहीं हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस कठिन समय में हर संभव मदद के लिए तुरंत कदम

उठाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अलग पत्र में खरगे ने कहा कि नेपाल में बाढ़ से गंभीर प्राकृतिक आपदा आई है। जान का नुकसान, घरों और बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विनाश और अनगिनत लोगों के विस्थापन ने प्रभावित समुदायों को बहुत परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने लिखा कि भारत के लोगों का नेपाल के लोगों के साथ गहरा और स्थायी रिश्ता है। दुख की इस घड़ी में भारत को मजबूती से अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होना चाहिए और इस तबाही से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देनी चाहिए।

खरगे ने सरकार से आग्रह किया कि नेपाल को तत्काल और व्यापक मानवीय और आपदा-राहत सहायता देने पर विचार किया जाए। खास तौर पर, नेपाल सरकार के साथ समन्वय में जहां भी जरूरत हो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को तैनात करने पर विचार किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, निकासी और राहत कार्यों में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में एनडीआरएफ की विशेषज्ञता और अनुभव जीवन बचाने और इस बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने में बहुमूल्य साबित हो सकती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि गृह मंत्रालय इस मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से देखेगा और बाढ़ प्रभावित नेपाल के लोगों तक भारत की सहायता पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

दिल्ली में सीएनजी की कीमत 3.89 रु. प्रति किया महंगी

नई दिल्ली । इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने ऑटो, कैब, बसों और किफायती पर्सनल कारों में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेसेड नेचुरल गैस (सीएनजी) 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से 3.89 रुपए महंगी हो जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में जहाँ आईजीएल काम करती है, अब इसकी कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। पब्लिक सेक्टर की कंपनी आईजीएल ने बताया कि इंटरनेशनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की कीमतें काफी ज्यादा हैं। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमत शनिवार से 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगी। आईजीएल ने जानकारी दी। आईजीएल ने एक बयान में बताया कि सीएनजी के लिए जरूरी गैस का एक बड़ा हिस्सा आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से पूरा किया जा रहा है।

वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण?

वाशिंगटन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रशासन ने वेनेजुएला के साथ एक बड़ा समझौता किया है। सोशल मीडिया पर समझौते की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज के बीच बातचीत के जरिए तय किया गया था। ट्रंप ने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी-अभी वेनेजुएला के साथ एक समझौता किया है, जो दुनिया के इतिहास में तेल का सबसे बड़ा सौदा है। ट्रंप ने कहा कि उनके देश ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस समझौते के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज ने बातचीत की थी।

सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं

नई दिल्ली । शनिवार (29 अगस्त 2026) को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पुराने रेट को बरकरार रखा है। वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 1 अगस्त को की गई कटौती के बाद वही कीमतें लागू हैं। तेल कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 से 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपए से लेकर 209 रुपए तक की कटौती की थी। दिल्ली में करीब 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कमी की गई थी। इसके बाद कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872.50 रुपए हो गई। इससे पहले 1 जुलाई को भी कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में करीब 183.50 रुपए तक की कटौती हुई थी।

स्टेल प्रमुख समाचार

महिला टी20 में थाईलैंड से आज भिड़ेगी भारतीय टीम

नईदिल्ली । ऐसे समय में जबकि टीम की



फॉर्म और निरंतरता पर सवाल उठ रहे हैं तब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को यहां महिला टी20 एशिया कप ग्रुप ए के अपने पहले मैच में थाईलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहेगी। पिछले एक दशक में महिला टी20 एशिया कप में भारत सबसे दबदबा बनाने वाली टीम रही है। उसने 2016-17 से इस टूर्नामेंट के टी20 प्रारूप के पांच संस्करणों में तीन बार खिताब जीता है लेकिन हाल में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

भारत ने इस साल खेले गए 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से नौ मैच हारे हैं। उसको आखिरी हार हाल में महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी।

ऐसे समय में जबकि कप्तान हरमनप्रीत के खुद की फॉर्म और सबसे छोटे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं तब भारत एशिया के दो प्रमुख टूर्नामेंट में खेलने की तैयारी कर रहा है। एशिया कप के तुरंत बाद जापान में एशियाई खेल होंगे। इन दोनों प्रतियोगिताओं में भारत खिताब के मजबूत दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा।

भारत को आठ टी20 वाली महिला टी20 एशिया कप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। हरमनप्रीत ने महिला टी20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन में हालांकि निरंतरता का अभाव है जो टीम के लिए चिंता का विषय है। एशिया कप और एशियाई खेलों के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स के बाहर होने के बाद भारत ने अपनी टीम में प्रतिका रावल को शामिल किया है, लेकिन टीम को मध्य क्रम में जेमिमा की कमी खलेगी।

दुर्गेश उपाध्याय

पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक यात्रा को करीब से देखते हुए मेरा मानना है कि हाल में जापानी प्रतिनिधिमंडल का उत्तर प्रदेश दौरा केवल निवेश से जुड़ी सामान्य खबरों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकातों से संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच संबंध अब अधिक गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहे हैं।

2017 से पहले इस तरह के उच्चस्तरीय संवाद अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते थे। उस समय कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल को लेकर बनी धारणा अक्सर विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तलाशने से रोकती थी।

हालिया बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है

क्योंकि निवेशकों की नजर में उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफी बदली है। कुछ समय पहले तक राज्य में निवेश की चर्चा शुरू होते ही बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और सरकारी विभागों के साथ काम करने में आने वाली दिक्कतों की बात सामने आती थी। आज बातचीत तेजी से इस ओर बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को क्या अवसर दे सकता है। मेरे निवेशकों से यह एक बड़ा बदलाव है, जिसके पीछे निर्णायक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निवेश आकर्षित करने और निवेशकों की राह आसान बनाने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है।

इस बदलाव के कई संकेत जमीन पर दिखाई देते हैं। नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और उभरते निवेश केंद्रों ने कारोबारियों के उत्तर प्रदेश को देखने का नजरिया बदला है।



इसके साथ ही प्रशासन के काम करने के तरीके में भी बदलाव आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निवेश को आसान बनाने और समयबद्ध निर्णय लेने को अपनी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। ऐसे समय में जापान की रुचि उत्तर प्रदेश के लिए खास मायने रखती है।

जापान के पास उन क्षेत्रों में लंबा अनुभव है, जिनमें उत्तर प्रदेश अब अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है- उन्नत विनिर्माण, इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीक, कौशल विकास और बेहतर उत्पादन व्यवस्था। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के पास वह

चीज है जिसकी बराबरी बहुत कम बाजार कर सकते हैं- बड़ा पैमाना। विशाल आबादी, तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, युवा कार्यबल और बेहतर होती कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश को उन कंपनियों के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाती है, जो पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों से आगे नए बाजार तलाश रही हैं।

हालांकि, उत्तर प्रदेश को इस संबंध को केवल आने वाले निवेश की राशि के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। असली अवसर जापानी विशेषज्ञता को राज्य के व्यापक औद्योगिक तंत्र का हिस्सा बनाने में है।

उत्तर प्रदेश में काम करने वाली जापानी कंपनियों को स्थानीय विक्रेता और सप्लायर नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे प्रदेश के एमएसएमई बड़े विनिर्माण नेटवर्क और सप्लाय चैन का हिस्सा बन सकेंगे। यदि उन्हें तकनीक, गुणवत्ता मानकों और प्रबंधन

प्रणाली के क्षेत्र में उचित सहयोग मिले, तो इनमें से कई उद्यम आगे चलकर जापान और वैश्विक सप्लाय चैन में भी अपनी जगह बना सकते हैं।

कौशल विकास एक और ऐसा क्षेत्र है, जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। उद्योग की वास्तविक जरूरतों से अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के बजाय उत्तर प्रदेश जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के साथ स्थापित कर सकता है, जहां वास्तविक निवेश आ रहा है। युवाओं को उद्योग की विविध जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने से रोजगार के नतीजे कई अधिक सार्थक होंगे। इस साझेदारी का एक सांस्कृतिक पक्ष भी है, जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के कारण उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है, जबकि जापान की बौद्ध विरासत में गहरी और निरंतर रुचि रही है।

केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है: सीएम साय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रख है

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य से नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए हर संभव सहयोग दिया है। श्री साय ने जोर देकर कहा कि पिछले वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नक्सलवाद का प्रभावी सफाया रहा है। साय शनिवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा एवं जन-समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आहूत प्रदेशस्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के गहरे आत्मीय संबंधों को रेखांकित किया और पुरानी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि राज्य निर्माण के समय नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले का सघन दौरा कर संगठन को मजबूती दी थी। यही कारण है कि

उनका छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना और अटूट नाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे निरंतर राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ स्वीकृत कर रहे हैं। साय ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब बस्तर सहित पूरे वनांचल क्षेत्र के वनवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जो लोग नक्सल प्रभाव के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, उन्हें अब बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्नत जीवन शैली का अधिकार मिल रहा है। इसी क्रम में श्री साय ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। साय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सेवा ही संकल्प अभियान के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लाभार्थियों तक पहुँचें। साय ने अपने सम्बोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता शिवप्रकाश को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ भी दीं।

सेवा ही संकल्प अभियान



भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव असम्भव को सम्भव कर दिखाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भूकम्प की त्रासदी शेल चुके गुजरात का पुनरुत्थान है। उन्होंने गुजरात को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में स्थापित कर एक मिसाल पेश की, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देश की जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मेक इन इंडिया की सफलता और 24 करोड़

से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना धरातल पर दिख रहे बदलाव का प्रमाण है। आज देश में विश्वस्तरीय रेलवे, अत्याधुनिक हवाई अड्डे और मजबूत राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। केन्द्र सरकार की नीतियों के केंद्र में महिला सशक्तिकरण रहा है। जन-धन खातों के जरिए सीधे लाभ, राशन कार्ड में महिला को परिवार का मुखिया बनाना और तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिया गया है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की

समाप्ति का साहसिक कदम हो या भव्य राम मंदिर निर्माण के दशकों पुराने संकल्प की सिद्धि, सरकार ने देश की आस्था और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिवप्रकाश ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी नरेंद्र मोदी संगठन सर्वोपरि की भावना का पालन करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में सामान्य कार्यकर्ता की भाँति बैठना और सभी संगठनात्मक प्रोटोकॉल का पालन करना

उनके अगाध समर्पण को दर्शाता है। मन की बात और परीक्षा पे चर्चा जैसे मंचों के जरिए प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग-बुजुर्गों से लेकर युवाओं और बच्चों तक-से निरंतर जीवन्त सम्पर्क बनाए रखते हैं। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा के ऐतिहासिक कार्यकाल के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियानों का विवरण साझा किया। डॉ. पाटीदार ने कहा कि यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनांदोलन बनेगा। इसमें हर गाँव, शहर, बूथ और परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. पाटीदार ने माहभर चलने वाले इस अभियान के कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि प्रत्येक बूथ पर हर परिवार दीप प्रज्वलन कर प्रधानमंत्री मोदी के 25

वर्षों के सेवा समर्पण के प्रति आभार प्रकट करेगा और विकसित भारत 2047 का संकल्प लेगा। 25 करोड़ बच्चों के सपनों के भारत के तहत राष्ट्रव्यापी ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिता के तहत देशभर के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में छात्रों के लिए मोदी सरकार के सेवा कार्यों और विकसित भारत की संकल्पना पर भाषण व ड्राइंग प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। इसी प्रकार नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर से वाराणसी जल का जन और सेवा संकल्प यात्रा, सेवा मेरा योगदान जिसके तहत 25 सेवा गतिविधियाँ, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज, जनसेवक महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉ. पाटीदार ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से आह्वान किया कि वे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा महाभियान से जुड़कर 25 वर्षों के सेवा कार्यों में से एक कार्य चुनकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने खेलों पर आधारित ‘हमारे खिलाड़ी’ का किया विमोचन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली खेल इतिहास और खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा कॉफी टेबल बुक 'हमारे खिलाड़ी' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित

छत्तीसगढ़ की खेल विभूतियों के जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और खेल जगत में उनके योगदान से संबंधित छायाचित्रों एवं जानकारीयों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेश के खेल इतिहास और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की इस पहल की सराहना की। खेलों पर आधारित इस विशेष फोटो प्रदर्शनी में शहीद राजीव पाण्डेय, शहीद पंकज विक्रम, शहीद कौशल यादव और शहीद विनोद चौबे सहित

मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस समारोह का आयोजन

रायपुर। भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रातः 8:30 बजे से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ हॉकी के महान खिलाड़ी एवं भारतीय खेल जगत के प्रेरणास्रोत मेजर ध्यानचंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में छात्र-छात्राओं को खेलकूद, योग एवं नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व एवं उनसे होने वाले शारीरिक तथा मानसिक लाभों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा दैनिक जीवन में खेल एवं व्यायाम को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के खेल अधिकारी डॉ. राम कुमार ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक "Physical Education, First Aid, Yoga and Meditation: A Practical Perspective" का विमोचन कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। पुस्तक में शारीरिक शिक्षा, प्राथमिक उपचार, योग एवं ध्यान से संबंधित विषयों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ आगमन पर रूपकुमारी चौधरी का भव्य स्वागत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नव-नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी का दायित्व ग्रहण करने के बाद शनिवार को प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर राजधानी रायपुर में ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया गया। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनके पहुँचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी, ढोल-ताशों और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया।



विमानतल पर स्वागत के पश्चात श्रीमती चौधरी सीधे एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय पहुँचीं। वहाँ उन्होंने स्मृति मंदिर में पार्टी के पितृ पुरुषों एवं प्रेरणास्रोत महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया और संगठन के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय

कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। एकात्म परिसर में स्वागत कार्यक्रम के उपरांत श्रीमती चौधरी भाजपा प्रदेश कार्यालय 'कुशाभाऊ ठाकरे परिसर' पहुँचीं। वहाँ उन्होंने स्मृति मंदिर में पार्टी के पितृ पुरुषों एवं प्रेरणास्रोत महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया और संगठन के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय

नेतृत्व द्वारा दी गई इस महती जिम्मेदारी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर यह अवसर मिलना केवल भाजपा में ही संभव है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'नारी शक्ति वन्दन' का दौर चल रहा है। संगठन में महिलाओं की भूमिका केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नीतियों के क्रियान्वयन और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में अग्रणी हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

उप मुख्यमंत्री साव ने 93 करोड़ के कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जशपुर कम्प्युनिटी हॉल में 93 करोड़ 91 लाख 98 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें अमृत मिशन 2.0 के तहत 86 करोड़ 99 लाख 21 हजार रुपए की पेयजल योजना और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 6 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपए लागत के एसटीपी का निर्माण शामिल हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जशपुर नगर के विकास के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपए के नए कार्यों की भी घोषणा की। इनमें जशपुर नगर पालिका कार्यालय के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, देशपांडे पार्क एवं तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 48 करोड़ रुपए, मटन मार्केट के लिए एक करोड़ 48 लाख रुपए और शिव वाहन के लिए 30 लाख रुपए की राशि शामिल है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत, जशपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगा राम भगत, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमैद सिंह और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय भी भूमिपूजन कार्यक्रम में मौजूद थे।

राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर मिर्जा एजाज़ बेग का किया गया अभिनंदन



रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य हज्र कमेटि के चेयरमैन मिर्जा एजाज़ बेग को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर राज्य हज्र कमेटि के चेयरमैन मिर्जा एजाज़ बेग को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। श्री मिर्जा एजाज़ बेग को राज्यमंत्री दर्जा दिए जाने से प्रदेश के मुस्लिम समाज एवम् सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। उन्हें राज्य मंत्री दर्जा दिए जाने से समाज एवं शुभचिंतकों में हर्ष व्याप्त है। श्री बेग ने राज्यमंत्री दर्जा दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल एवं प्रदेश भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया है।

बिजली के निजीकरण की तैयारी जनता के साथ विश्वासघात है: कांग्रेस

रायपुर। बिजली के निजीकरण की तैयारी जनता के साथ विश्वासघात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर, 400 यूनिट तक मिलने वाली राहत को खत्म कर और स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के बाद अब बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। जनता के खून-पसीने की कमाई से खड़ी की गई बिजली कंपनी को बेचने और निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का ठेका देने की सरकार की तैयारी छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के साथ सीधा विश्वासघात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पहले मंत्रिमंडल में विद्युत कंपनी के शेयर बेचने का फैसला लिया गया और अब निजी कंपनी को बिजली सप्लाई का ठेका देने की तैयारी की जा रही है। जब सरकारी बिजली कंपनी प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध करा रही है तो उसे कमजोर कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हर परिवार, किसान, मजदूर और छोटे व्यवसाय की बुनियादी जरूरत है। बिजली व्यवस्था का निजीकरण हुआ तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं को जेब पर पड़ेगा और भविष्य में बिजली के दाम बढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा।

जिले के 17 नवीन सहकारी समितियों के लिए भूमि आर्बिट्रट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत जिला दुर्ग की प्राथमिकता कृषि साख सहकारी सोसायटी की पुनर्गठन योजना 2025 अनुसूची-02 में अंकित 31 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा 17 प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए भूमि आर्बिटन की स्वीकृति दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धमधा विकासखंड अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मार्या पथरिया पंजीयन क्रमांक 3421 के लिए 1.00 हेक्टेयर भूमि, सेवा सहकारी समिति मर्यादित पुरेदा पंजीयन क्रमांक 3422 के लिए 1.20 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित अरसी पंजीयन क्रमांक 3423 के लिए 1.34 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित दारगांव पंजीयन क्रमांक 3426 के लिए 1.00 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित हिरैतरा पंजीयन क्रमांक 3434 के लिए 1.25 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित भांडाकोकड़ी पंजीयन क्रमांक 3435 के लिए 0.69 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित नंदवाय पंजीयन क्रमांक 3427 के लिए 1.20 हेक्टेयर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित मलपुरीकला पंजीयन क्रमांक 3433 के लिए 2.50 हेक्टेयर एवं सेवा सहकारी समिति मर्यादित सेमरिया पंजीयन क्रमांक 3429 के लिए 1.20 हेक्टेयर शासकीय भूमि आर्बिटन की गई है।

यातायात पुलिस ने 10 ठेले किए जप्त



रायपुर। पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल, पुलिस कमिश्नरेंट रायपुर डॉ. अर्चना झा के निर्देशानुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सामने सड़क किनारे एवं आसपास लगने वाले ठेले-खोमचे के कारण उत्पन्न हो रही यातायात संबंधी समस्याओं को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध श्री भुनेश्वर साहू द्वारा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर नगर निगम की टीम 'प्रहरी' के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान के दौरान एम्स के सामने सड़क किनारे एवं आवागमन क्षेत्र में अव्यवस्थित रूप से लगाए गए ठेले-खोमचे एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान 10 ठेलों को जप्त किया गया, जबकि लगभग 15 से 20 ठेले-खोमचे संचालकों को मौके से हटाया गया।

वरिष्ठ शिक्षकों, मेधावी विद्यार्थियों और रोजगार प्राप्त युवाओं का सम्मान

जुनून और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी : राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका आज बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम चाम्पा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित लोकार्पण एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के नवनिर्मित सभाकक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही, वरिष्ठ शिक्षकों, 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों, पीएटी में चयनित विद्यार्थियों और हम होंगे कामयाब योजना के तहत रोजगार प्राप्त 9 युवाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि नवनिर्मित सभाकक्ष से



विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने शिक्षक-छात्र संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर देते

हुए कहा कि शिक्षकों को अपने आचरण से छात्रों का रोल मॉडल बनना चाहिए। छात्रों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुनून पैदा करें और उसे

हाकीत में बदलने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करें। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह नीति कौशल विकास और विषय विशेषज्ञता हासिल करने में सहायक है। मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपील की कि वे तकनीक का इस्तेमाल केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही करें। सोशल मीडिया और एआई (ट्यू) सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग आत्ममंथन और सृजनात्मक को कम कर देता है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने राज्यपाल के आगमन को चाम्पा

गांव के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि शिक्षक न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध भी कराते हैं। उन्होंने छात्रों को असफलताओं से न चकराकर कड़ी मेहनत जारी रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ? राज्यपाल ने अपनी स्वर्गीय माता चम्पावती डेका की स्मृति में स्कूल परिसर में अमलताश का पौधा रोपा। राजस्व मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण किया।



समन्वय जैसे जीवन-मूल्यों का बीजारोपण होता है। ये गुण न केवल व्यक्तित्व को संतुलित और बहुआयामी बनाते हैं, बल्कि आज के दौर में तनाव मुक्त जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में परिसर में विविध पारंपरिक एवं नवाचारी खेलों की धूम रही। इसमें विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने 'ऑकार दौड़', संख्या में छात्र-छात्राएँ मौजूद रहे।